सांध्य दैनिक
# नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

पेज 7 में ▸▸ फिल्म द ग्रेट स्केटः फरार में...

✦ वर्ष -01 ✦ अंक- 07 ✦ दुर्ग, बुधवार 21 जनवरी 2026 ✦ ✦ पृष्ठ- 08 ✦ मूल्य- 2 रुपए ✦ संपादक- अलोक तिवारी ✦ PRGI Reg No : CTHIN/25/A3746

## न्यूज Window

### अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, पीड़िता ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

**नई दिल्ली।** दिल्ली की एक सत्र अदालत द्वारा बलात्कार के एक मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता और उनके अधिवक्ताओं ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी जांच की विश्वसनीयता, गति और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। पीड़िता के साथ उनके कानूनी प्रतिनिधियों—असग़र खान एंड एसोसिएट्स और ब्लैकथॉर्न चैंबर्स—ने संबोधित किया। इस दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता असग़र खान, नजमी खान, अब्दुल ताहिर खान, सहर मसरूर और मोहद. वासिल खान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। यह मामला एफआईआर संख्या 300/2025 से संबंधित है, जो वसंत विहार थाना में भारतीय न्याय संहिता (ब्नहस्) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। एफआईआर में शरत वोहरा को आरोपी नामित किया गया है। आरोपों में विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार, यौन शोषण और आपराधिक धमकी शामिल हैं। कानून के प्रावधानों के अनुरूप पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है। पीड़िता के अधिवक्ताओं ने बताया कि 14 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली की सत्र अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने यह आदेश न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अध्यक्षता में पारित किया, जिसमें रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का विस्तार से अवलोकन किया गया। पीड़िता ने यह आशंका भी जताई है कि गिरफ्तारी में लगातार हो रही देरी से आरोपी के फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बढ़ रही है।

उनके अधिवक्ताओं का कहना है कि समय पर गिरफ्तारी और कानून का सख्त अनुपालन ही न्याय सुनिश्चित कर सकता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रख सकता है।

### चिकन नेक के करीब चीन की मौजूदगी बढ़ी, तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर भारत-बांग्लादेश रिश्तों में नया तनाव

**ढाका।** भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जमी बर्फ और गहराती नजर आ रही है। इसी बीच चीन के बांग्लादेश स्थित राजदूत याओ वेन ने सोमवार को तीस्ता नदी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया, जो भारत के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी 'चिकन नेक' के काफी करीब स्थित है। यह करीब 22 किलोमीटर लंबी संकरी पट्टी है, जिसके जरिए भारत की मुख्य भूमि पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई है। यह दौरा तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत चल रही तकनीकी जांच से जुड़ा बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ नेताओं द्वारा पिछले साल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 'लैंडलॉक्ड' कहे जाने और चीन के आर्थिक विस्तार का समर्थन करने जैसे बयान दिए गए थे, जिन पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश की जल संसाधन सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने चीनी राजदूत याओ वेन के साथ रंगपुर के तेफामधुपुर तालुक के शाहबाजपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन तीस्ता मास्टर प्लान (टीएमपी) को जल्द से जल्द लागू करने के लिए उत्सुक है।

### 3 दिन में सरेंडर करो नहीं तो', ईरान ने प्रदर्शनकारियों को दिया अल्टीमेटम

**तेहरान।** बीते साल दिसंबर के अंत में शुरू हुए प्रदर्शनों ने ईरान को हिलाकर रख दिया था। अब हालात काफी हद तक शांत हो गए हैं और खामेनेई शासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने सोमवार को 'दंगाइयों' को तीन दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साथ ही यह भी कहा है कि वह उन आर्थिक समस्याओं से निपटेगी, जिनकी वजह से प्रदर्शन भड़के थे। हालांकि मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि प्रदर्शन दबाने की कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं।

# हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणीः उदयनिधि के 'सनातन मिटाओ' बयान में नरसंहार के संकेत

■ चेन्नई (एजेंसी)

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सोमवार को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के उस बयान पर सख्त टिप्पणी की, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक संबोधन में सनातन धर्म का सफाया करने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान नरसंहार की मांग जैसा है। हाईकोर्ट की पीठ ने भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया।

मदुरै पीठ की जस्टिस एस श्रीमति ने अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश देते हुए कहा, 'अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का समूह यहां नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सही शब्द 'नरसंहार' है। अगर सनातन धर्म एक धर्म है तो यह धर्मसंहार है। इसका मतलब है किसी भी तरीके से या अलग-अलग तरीकों से किसी धर्म को मानने वाले लोगों को खत्म करना है, जिसमें पर्यावरणीय विनाश, तथ्य विनाश, संस्कृति विनाश (सांस्कृतिक नरसंहार) जैसे हमले शामिल हैं। इसलिए, तमिल शब्द 'सनातन ओझिप्पु' का साफ मतलब नरसंहार या संस्कृति विनाश होगा।'

#### उदयनिधि स्टालिन की किस टिप्पणी पर हुआ था विवाद

सितंबर 2023 में 'सनातन अबोलिशन कॉन्फ्रेंस' नामक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफविवादित टिप्पणी की थी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों को सिर्फरोकना ही जरूरी नहीं है बल्कि इन्हें मिटा देना चाहिए। इसी तरह सनातन धर्म का भी सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कैप्शन में सवाल किया था कि क्या ये बयान भारत की 80 फीसदी जनसंख्या के नरसंहार की मांग जैसा नहीं है? इस पोस्ट को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफएफआईआर दर्ज की थी। जिसके खिलाफ अमित मालवीय ने अदालत का रुख किया।

# संगठन संस्कार है, सत्ता नहीं—साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की यात्रा पर नया संकल्प

### संगठन पूरी एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा- पीएम मोदी

■ (आलोक तिवारी)नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने पहले संदेश में संगठन की आत्मा, कार्यकर्ता की ताकत और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को स्पष्ट शब्दों में रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक संस्कार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए संगठन पूरी एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। उन्होंने जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में भाजपा ने संगठनात्मक विस्तार, सेवा की संस्कृति और कार्यकर्ता-आधारित राजनीति को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया।

अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह देश की एकमात्र पार्टी है जहाँ बड़े पदों के लिए किसी विशेष परिवार से होना जरूरी नहीं, बल्कि साधारण कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ी योग्यता है। यही कारण है कि भाजपा में एक सामान्य परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे दायित्व तक पहुँच सकता है। उन्होंने भाजपा की वैचारिक यात्रा को स्मरण करते हुए कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान, पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व से प्रेरित यह संगठन हमेशा राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर आगे बढ़ा है।

### ठेकेदार को लाभ पहुंचाने बड़ी गड़बड़ी की आशंका

## कचरे से खाद बनाने 29.50 लाख रुपए ज्यादा में दिया ठेका और वसूली राशि 9.27 लाख रुपए घटा दिए

**भिलाई।** स्वच्छ भारत मिशन पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना कचरे से खाद बनाने के लिए बड़ी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। आशंका जताई जारही है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा खेल खेला गया है। जिसकी वजह से नगर निगम को बड़ी हानि हुई है। जबकि चौकाने वाली बात यह है कि कचरे से खाद बनाने के लिए निगम ने ठेकेदार को 5.77 करोड़ रुपए में ठेका दिया था, उसी काम को शासन के आदेश पर अब निगम ने ही 2.66 करोड़ में दिया है। मतलब निगम ठेकेदार को 3.15 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट किया है।

सेग्रीगेशन प्लांट में कचरे से खाद बनाने के लिए ठेका किया गया। तब ठेकेदार को लाभ पहुंचाने एक ओर जहां 29.50 लाख रुपए अधिक रेट में ठेका दिया गया। वहीं दूसरी ओर खाद के एवज में ठेकेदार से निगम जो राशि कटौती करता है, उस राशि को 9.27 लाख कम कर दिया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को 38.77 लाख रुपए वा??र्षिक लाभ पहुंचा गया और निगम को आ?र्थिक क्षति पहुंचाई गई है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज के आधार पर नगर निगम? भिलाई के पास शहर में 9 एसएलआरएम सेंटर है। जिसका पहला टेंडर 2 फरवरी 2023 को जारी किया गया। टेंडर में किसी एजेंसी ने भाग नहीं लिया। तब ?रि-टेंडर 17 फरवरी 2023 को किया गया।? जिसमें मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर और मे. शम्भू सिंह कन्ट्रक्शन सेक्टर 2 ने टेंडर भरा। तकनीकी समिति ने मे. शम्भू सिंह कन्ट्रक्शन का दस्तावेज कम होना बनाकर टेंडर से बाहर कर दिया। तो सिर्फ मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर ही बचा। जिसे ठेका दे दिया गया। मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर ने ऑनलाइन रेट 1130 रुपए प्रति टन भरा था। वार्षिक दर 10.84 करोड़ रुपए था।

### मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक

### अलग-अलग हेल्पलाइन से छुटकारा, दिल्ली में भी 112 बनेगा एकमात्र आपात नंबरः सीएम रेखा गुप्ता

**नई दिल्ली।** दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी, त्वरित और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अब दिल्ली में किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति में अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे। किसी भी तरह की आपात स्थिति में सिर्फ 112 डायल करने पर तेजी से मदद पहुंचेगी। इसकी शुरुआत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) 2.0 के तहत की गई है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को संकट की घड़ी में अलग-अलग नंबर याद रखने की परेशानी से मुक्त करना और उन्हें तेजी से सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में पुलिस (100), अग्निशमन सेवा (101), एंबुलेंस/स्वास्थ्य सेवा (108), महिला सहायता (181), बाल सहायता (1098), गैस रिसाव (1906), बिजली आपूर्ति (19123), जल आपूर्ति (1916), दिल्ली मेट्रो (155370) और आपदा प्रबंधन/राहत सेवाओं (1077) सहित कई आपात सेवाओं के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं।

### आधिकारिक मुहर 27 जनवरी को लगने की उम्मीद

# 'मदर ऑफऑल डील्स' की दहलीज पर भारत; 27 जनवरी को ऐतिहासिक समझौते के आसार

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं के बीच भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) एक 'ऐतिहासिक व्यापार समझौते' के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान संकेत दिया कि दोनों पक्ष इस बहुप्रतीक्षित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं। इसे कुछ हलकों में मदर ऑफऑल डील्स कहा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का निर्माण करेगा।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अपने संबोधन में साफकिया कि यह समझौता महज एक कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा। इस दौरान विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा, भारत और यूरोप के बीच अब तक का सबसे बड़ा समझौता बस होने ही वाला है।

**विशाल दायरा:** इस समझौते से दो अरब लोगों का एक साझा बाजार तैयार होगा।

**आर्थिक ताकत:** यह संयुक्त बाजार वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से का

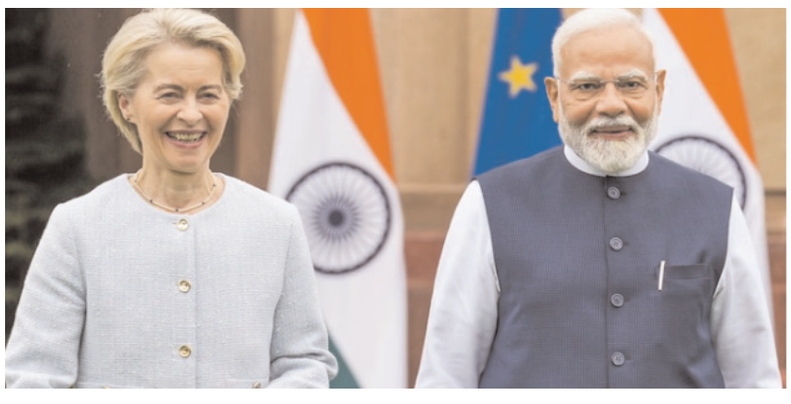

प्रतिनिधित्व करेगा।

**यूरोप का फोकस:** वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप आज के 'ग्रोथ सेंटर्स' और इस सदी के आर्थिक पावरहाउस यानी भारत के साथ कारोबार करना चाहता है। उन्होंने इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और गतिशील महाद्वीपों में से एक के साथ जुड़ने के लिए यूरोप का 'फर्स्ट-मूवर एडवांटेज' बताया।

माना जा रहा है कि सरकार एफ्टीए पर गणतंत्र दिवस के दौरान बड़ी घोषणा की तैयारी कर रही है। इस पर आधिकारिक मुहर 27 जनवरी को लगने की उम्मीद है।

**विशेष दौरा:** यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। वे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

**समिट वार्ता:** 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर वार्ता में इस एफ्टीए (स्नञ्ज) के संपन्न होने की घोषणा की जा सकती है।

व्यापार के अलावा, इस समिट में रक्षा और सुरक्षा पर भी बड़ा फेकस रहेगा। भारत और ईयू एक 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' (एसडीपी) का अनावरण कर सकते हैं।इसमें ये चीजें शामिल होंगीं।-

**फंडिंग तक पहुंच:** प्रस्तावित एसडीपी के तहत भारतीय कंपनियों के लिए श्च के 'एसएएफई' कार्यक्रम में भाग लेने के रास्ते खुलेंगे। एसएएफई यूरो 150 बिलियन का एक वित्तीय साधन है, जो रक्षा तैयारी को तेज करने के लिए बनाया गया है।

**ज्एसओआईए समझौता:** दोनों पक्ष औद्योगिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 'सूचना सुरक्षा समझौते' के लिए बातचीत शुरू करेंगे।

अमेरिका की टैरिफ नीतियों का असर यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब वाशिंगटन (अमेरिका) की टैरिफ नीतियों और व्यापारिक व्यवधानों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ रही हैं।

### साहित्य महोत्सव को लेकर आम-लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा

## साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान

■ भिलाई (नई दृष्टिबिंदु)

बसंत पंचमी 23 जनवरी से नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में तीन दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश भर के 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होने जा रहे हैं। इस तीन दिवसीय उत्सव से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरा प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को साहित्यिक जगत में एक नई पहचान प्रदान करेगा तथा जनसमुदाय को साहित्य, लेखन और पठन-पाठन की ओर प्रेरित करेगा। साहित्य महोत्सव के दौरान साहित्य विमर्श खुले संवाद, समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श होगा। साहित्य महोत्सव को लेकर आम-लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज जब सोशल मीडिया के कोलाहल में ज्ञान की धारा अक्सर सूचनाओं के शोर में दब जाती है। ऐसे समय में साहित्य उत्सव एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। जहां विचार-विमर्श के बीच संवाद की संस्कृति जीवित रहती है। सृजन वही जन्म लेता है, जहां मन खुला हो और कथा वही आकार लेती हैं जहां मनुष्य अपने सत्य से संवाद करने का साहस रखता है। साहित्य महोत्सव के लोगो (डिजाइन) में अंकित ''आदि से अनादि'' तक वाक्य साहित्य के उस अटूट यात्रा को दर्शाता है, जिसमें आदिकालीन रचनाओं से लेकर निरंतर विकसित हो रहे आधुनिक साहित्य तक सभी रूप समाहित हैं।

साहित्य कालातीत है, वह समय, समाज भाषा और पीढ़ियों को जोड़कर चलने वाली निरंतर धारा है। तीन दिनों तक पुरखौती मुक्तांगन में साहित्यिक संवाद, पुस्तक विमोचन, विचार-मंथन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कला-प्रदर्शनियों का जीवंत केंद्र बनेगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय साहित्यिक मानचित्र पर एक सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सांस्कृतिक गर्व का विषय है क्योंकि इसमें राज्य की हजारों साल पुरानी साहित्यिक जड़े, जनजातीय परंपराएं, सामाजिक समरसता और आधुनिक रचनात्मक दृष्टि सभी का सुंदर सार्थक और कलात्मक संगम दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक यात्रा आदि से अनादि तक अविचल, जीवंत और समृद्ध रही है, और आगे भी इसी धारा में निरंतर विकास की नई कहानियां लिखती रहेंगी। साहित्य उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे, इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र और 3 संवाद सत्र आयोजित किये जाएंगे।

# मुंगेली में धान खरीदी घोटाले का बड़ा खुलासा, 8.14 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया

### राइस मिलर, समिति प्रबंधक सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार

### फर्जी वाहन, ओवरलोडिंग और रिसायक्लिंग से शासन को नुकसान

**रायपुर।** मुंगेली जिले में धान खरीदी और परिवहन व्यवस्था में हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई में 8 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में राइस मिलर संचालक, समिति प्रबंधक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर की गई जांच में यह सामने आया कि धान परिवहन के दौरान फर्जी वाहनों, अत्यधिक ओवरलोडिंग और रिसायक्लिंग के जरिए संगठित तरीके से शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जांच में यह भी उजागर हुआ कि धान उठाव करने वाले वाहनों की वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक अधिक ओवरलोडिंग कर अवैध परिवहन दर्शाया गया।

### कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर संयुक्त जांच

कलेक्टर श्री कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विस्तृत जांच की। जांच में राइस मिलरों, समिति प्रबंधकों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, पीडीएस चावल का वितरण नहीं करने, फर्जी वाहन नंबरों से परिवहन दिखाने और वास्तविक मात्रा से अधिक धान उठाव दर्शाने के ठोस प्रमाण मिले हैं।

प्रारंभिक जांच में करीब 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी और परिवहन में अनियमितताओं के साक्ष्य सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि नवागांव घुठेरा समिति ने उपलेटा राइस मिल से मिलीभगत कर 74 जीपीएस युक्त और 40 से अधिक बिना जीपीएस वाहनों के जरिए अवैध परिवहन किया।

इसी प्रकार सिंघनुपरी उपार्जन केंद्र द्वारा एसएस फूड के साथ मिलकर 4,542 क्विंटल धान का बिना जीपीएस वाहन से परिवहन छटन उपार्जन केंद्र द्वारा दीपक राइस मिल और नवकार मिल के साथ मिलकर 3,589 क्विंटल धान का अवैध परिवहन झगरहट्टा उपार्जन केंद्र द्वारा वर्धमान राइस मिलर्स के साथ अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब्दुल सत्तार पिता गुलाम कादर (निवासी दाउपारा), विकास पाण्डेय पिता विनय पाण्डेय (भटगांव-मुंगेली), महावीर जैन पिता ललित जैन, संतोष साहू पिता बलदाऊ एवं श्रीधर परिहार पिता हितकिशोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब्दुल समद, ललित जैन, नवेन्द मेनन और अनिल जांगड़े फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। धान उपार्जन में अनियमितताओं को लेकर थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 12/2026 तथा थाना लालपुर में अपराध क्रमांक 09/2026 के तहत भी फर्जी परिवहन और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं।

# इलेक्ट्रिक वाहनों से स्वच्छ भविष्य की ओर छत्तीसगढ़ का सशक्त कदम

### कोरबा में ई-व्हीकल प्रोत्साहन योजना बनी हरित परिवहन की मिसाल

**रायपुर।** पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना कोरबा जिले में हरित परिवहन की ओर एक मजबूत और प्रभावी पहल के रूप में सामने आई है। जिले में पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की संख्या लगभग चार लाख होने से बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती रहा है, जिसे इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से कम करने में यह योजना अहम भूमिका निभा रही है।

योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन क्रय करने पर वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा द्वारा डीलर प्वाइंट पंजीयन के दौरान वाहन स्वामी के बैंक विवरण संकलित कर ई-व्ही पोर्टल में प्रविष्टि की जाती है तथा आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि का पारदर्शी तरीके से अंतरण सुनिश्चित किया जाता है।

### एक साल में 3.27 करोड़ की सब्सिडी वितरित

1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में कोरबा जिले के 1774 वाहन स्वामियों को कुल 3 करोड़ 27 लाख 3 हजार 865 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। नागरिकों की बढ़ती रुचि और योजना की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 के लिए 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता का असर पंजीयन आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2024 में जहां 1244 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए थे, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 1488 हो गई। विशेष रूप से दोपहिया, तिपहिया और यात्री वाहनों की श्रेणियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, जो आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाती है।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

# कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम को लेकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

**दुर्ग।** महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 एवं शी-बॉक्स पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 19 जनवरी 2026 को शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय परिसर में किया गया।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति तथा जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति के गठन की अनिवार्यता की जानकारी दी गई। बताया गया कि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति में वह संबंधित कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष अथवा शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है।

### शिकायत प्रक्रिया व समिति की भूमिका पर जोर

कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत प्राप्त होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी शासकीय एवं निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। समिति का गठन नहीं करने पर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। साथ ही सभी कार्यालयों को अपनी आंतरिक शिकायत समिति को शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए, ताकि शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह प्रतिषेध, सखी वन स्टॉप सेंटर एवं महिला सशक्तिकरण केंद्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी दी गई और महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी, आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

# जल जीवन मिशन देवरी में दम तोड़ता नजर आया, करोड़ों खर्च के बाद भी गांव प्यासा

### घटिया निर्माण, लीकेज और अधूरी पाइपलाइन से ग्रामीणों में आक्रोश




**आरंग।** केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन (हर घर जल) योजना आरंग विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरी में भ्रष्टाचार, तकनीकी खामियों और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ग्रामीणों को घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के तहत 1 करोड़ 04 लाख 28 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत दावों के बिल्कुल विपरीत है।

योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन नवनिर्मित पानी टंकी से लगातार पानी का रिसाव (लीकेज) हो रहा है। इसके साथ ही पाइपलाइन विस्तार में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर पाइप फूट चुके हैं, जिससे लाखों लीटर पानी गलियों में बहकर बर्बाद हो रहा है। इन्हीं खामियों के कारण पिछले 10 से 15 दिनों से गांव की जलापूर्ति पूरी तरह ठप पड़ी है और ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं।

### सुरक्षा मानकों की अनदेखी, हादसे का खतरा

योजना में सुरक्षा मानकों की भी खुलेआम अनदेखी की गई है। पंप हाउस का निर्माण अब तक नहीं किया गया, जिसके चलते बिजली के कनेक्शन खुले में पड़े हैं। वहीं, टंकी परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं होने से वहां हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। विशेषकर बच्चों और मवेशियों के लिए यह क्षेत्र जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन भले ही 'हर घर जल' का दावा कर रहा हो, लेकिन ग्राम देवरी के कई वार्डों और घरों तक पाइपलाइन पहुंची ही नहीं है। इस संबंध में ग्राम पंचायत देवरी के सरपंच प्रतिनिधि टेकचंद साहू ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद न तो विभाग और न ही ठेकेदार कोई ठोस कदम उठा रहे हैं।उन्होंने कहा, करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी हमें दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।हैरानी की बात यह है कि निर्माण कार्य में मौजूद गंभीर खामियों के चलते अब तक इस योजना को ग्राम पंचायत देवरी को हैंडओवर नहीं किया गया है। तकनीकी रूप से अधूरा कार्य होने के बावजूद इसे कागजों में पूरा कैसे दर्शाया जा रहा है, यह बड़ा जांच का विषय बन गया है।

बार-बार शिकायतों के बावजूद मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी और पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने अब उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

### ठेकेदार और विभाग का पक्ष

इस मामले में जब संवाददाता ने ठेकेदार संजय कुमार अग्रवाल से संपर्क किया तो उन्होंने कर्मचारियों को भेजकर टंकी और पाइपलाइन की मरम्मत कराने की बात कही। वहीं पीएचई विभाग की उप अभियंता रानू दिनकर ने कुछ तकनीकी कारणों से योजना का हैंडओवर नहीं होने की बात स्वीकार की, हालांकि उन्होंने इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया।

# 22 जनवरी को लगेगा प्लेसमेंट कैम्प, निजी क्षेत्र के 126 पदों पर भर्ती

### 10वीं से स्नातक तक के अभ्यर्थी होंगे शामिल

**दुर्ग।** जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग, मालवीय नगर चौक में गुरुवार, 22 जनवरी 2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के दो नियोजकों द्वारा कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

प्लेसमेंट कैम्प में कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के 100 पद, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 10 पद, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के 5 पद, सेल्स एडवाइजर के 5 पद तथा ड्राइवर के 6 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 8,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन निर्धारित किया गया है।

इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा एवं किसी भी विषय में स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को प्लेसमेंट कैम्प में उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी द्रह्रश्चद्दद्ध्रड्डह्ल.ष्द्ध.द्दश्1.द्धठ्ठ, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप अथवा रोजगार कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, अंकसूची, पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस), रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लानी होगी। यह प्लेसमेंट कैम्प स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

# दुर्ग संभागः प्रशासनिक सुदृढ़ता और पर्यटन संभावनाओं का संगम

संदीप सिंह

**दुर्ग।** दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, औद्योगिक विकास और समृद्ध पर्यटन विरासत एक साथ दिखाई देती है। राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित यह संभाग न केवल शासन-प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएँ समेटे हुए है।

### प्रशासनिक संरचना और महत्व

वर्ष 2013 में गठित दुर्ग संभाग में कुल पांच जिले—दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और कवर्धा (कबीरधाम) शामिल हैं।

यह संभाग चार प्रमुख नगर निगमों का केंद्र है, जिससे नगरीय प्रशासन, औद्योगिक प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं की मजबूत व्यवस्था स्थापित हुई है। दुर्ग और भिलाई नगर निगम राज्य के सबसे विकसित शहरी क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार देखने को मिलता है।

### औद्योगिक आधार और कनेक्टिविटी

भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग संभाग की औद्योगिक पहचान है, जिसने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (पूर्व ह॥-6) एवं 30, साथ ही हावड़ाङ्कमुंबई रेल मार्ग, इस संभाग को देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ते हैं, जिससे प्रशासनिक संचालन और पर्यटन आवागमन दोनों को गति मिलती है।

### पर्यटन की अपार संभावनाएँ

दुर्ग संभाग प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का समृद्ध केंद्र है— भोरमदेव मंदिर (कवर्धा) 11वीं शताब्दी का यह मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। शिवनाथ नदी – धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन का प्रमुख आधार। मैत्री बाग, भिलाई – पारिवारिक एवं शैक्षणिक पर्यटन का केंद्र। राजनांदगांव ऐतिहासिक स्थल – सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण। ग्रामीण और जनजातीय पर्यटन ङ्क बालोद और बेमेतरा क्षेत्रों में लोकसंस्कृति आधारित पर्यटन की व्यापक संभावनाएँ।

### कृषि और भू-जल संपदा

दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिले भू-जल समृद्ध (भू-आवेशित) जिले हैं। शिवनाथ नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिससे कृषि आधारित पर्यटन (एग्रो-टूरिज्म) को भी बढ़ावा मिल रहा है।

### ऐतिहासिक विरासत

दुर्ग संभाग का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है— 1906 में दुर्ग जिला गठन, 1741 में मराठों द्वारा कलचुरी किले पर अधिकार, गुप्तकालीन सिक्कों की प्राप्ति (बानावरद क्षेत्र), यह विरासत पर्यटन को ऐतिहासिक गहराई प्रदान करती है।

### भविष्य की दिशा

मजबूत प्रशासनिक ढांचे, बेहतर सड़क-रेल संपर्क और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के कारण दुर्ग संभाग को पर्यटन एवं निवेश के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यदि योजनाबद्ध ढंग से धार्मिक, ऐतिहासिक और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन मिले, तो यह संभाग राज्य की अर्थव्यवस्था में और भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

### 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

# हिंदू युवा मंच ने निकाला 'भ्रष्टाचार का बजट' आंदोलन, नगर निगम भिलाई का किया घेराव

**भिलाई।** नगर निगम भिलाई में कथित भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हिंदू युवा मंच (वैशाली नगर भिलाई) द्वारा मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मंच के लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता घड़ी चौक से रैली के रूप में रवाना होकर नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य गेट तक पहुंचे, जहां 'भ्रष्टाचार का बजट' नाम से प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई।

रैली नगर निगम गेट पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इसके पश्चात मंच के पदाधिकारियों ने आयुक्त नगर निगम भिलाई के नाम एक 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम में हो रहे कथित खुलेआम भ्रष्टाचार पर गंभीर आरोप लगाए। आयुक्त की ओर से समस्याओं के शीघ्र निराकरण के आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल समाप्त किया गया, हालांकि मंच ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।




### ईएसआई- पीएफ से लेकर संपत्ति कर तक उठे सवाल

ज्ञापन में हिंदू युवा मंच ने आरोप लगाया कि नगर निगम भिलाई के अंतर्गत लगभग 2700 प्लेसमेंट कर्मचारी (सफाई, बोरिंग संधारण, गार्ड, फिल्टर प्लांट, सेग्रीगेशन प्लांट, पंप संधारण आदि) कार्यरत हैं, जिन्हें ईएसआई और पीएफ के बिना भुगतान किया जा रहा है, जो भारत सरकार के अधिनियम 2011 का उल्लंघन है।

मंच ने बड़े संस्थानों पर करोड़ों रुपये के बकाया संपत्ति कर पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आम जनता पर तो सख्ती होती है, लेकिन बड़े संस्थानों को संरक्षण दिया जा रहा है।

### वृक्षारोपण, पेवर ब्लॉक और फिल्टर प्लांट में भ्रष्टाचार का आरोप

हिंदू युवा मंच ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में 70 वार्डों में वृक्षारोपण के नाम पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह 15वें वित्त आयोग के तहत बीते चार वर्षों में 35 से 40 करोड़ रुपये के पावर ब्लॉक कार्यों में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, जिनकी शिकायत सामान्य सभा में कई बार उठाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

फिल्टर प्लांट के संधारण, पाइपलाइन बिछाने और पसंदीदा ठेकेदारों को कार्य देने को लेकर भी मंच ने गंभीर सवाल खड़े किए।

### शिक्षा कर, अधिभार और अन्य मुद्दे

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि नगर निगम द्वारा शिक्षा कर के नाम पर करोड़ों रुपये की वसूली की जा रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नजर नहीं आ रहा है।साथ ही संपत्ति कर में 18 प्रतिशत अधिभार और 1000 रुपये पेनल चार्ज को जनविरोधी बताते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग की गई।

इसके अलावा सुपेला देशी शराब भट्टी को हटाने, संजय नगर सुपेला ग्राउंड की बिक्री पर रोक, वार्ड क्रमांक 16 के शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण में डेढ़ करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार, सिटी बस और ई-रिक्शा संचालन में अनियमितताओं की जांच की मांग भी की गई।

### कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन तेज

हिंदू युवा मंच भिलाई महानगर अध्यक्ष कमल रणदिवे ने कहा कि यदि नगर निगम प्रशासन ने जल्द इन 11 बिंदुओं पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो मंच शहरव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान मंच कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन और महापौर की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन निगम प्रशासन के लिए यह आंदोलन एक कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

# 12 दुकानों पर लगा सील, बकाया किराया नहीं जमा करना पड़ा भारी

**दुर्ग।** नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम दुर्ग ने गंज पारा स्टेट बैंक के पीछे आबंटित दुकानदारों द्वारा नियमित किराया जमा नही किया जा रहा है, निगम के बाजार विभाग अमला द्वारा 12 दुकानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर निगम प्रभारी बाजार अधिकारी अभ्यूदय मिश्रा,सहायक शशिकांत यादव, सहायक ईश्वर वर्मा के नेतृत्व में की गई। इस दौरान बाजार विभाग एवं राजस्व विभाग टीम भी मौजूद रही। बकाया किराया जमा न होने पर हुई कार्रवाई नगर निगम के अनुसार,गंजपारा स्टेट बैंक के पीछे आबंटित 12 दुकानों को लीज पर आवंटित किया गया था और प्रत्येक दुकान पर प्रतिमाह निर्धारित किराया जमा करने का

प्रावधान था। बाद में किराए में वृद्धि की सूचना भेजकर दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अधिकांश दुकानदार समय पर भुगतान नहीं कर सके। सील की गई 12 दुकानों पर निगम का किराया बकाया था।द अनोटिस अवधि पूरी होने के बाद दुकानों का आवंटन निरस्त कर दुकानों को सील किया गया। मोहम्मद हसन खान / मतिक खान स्टेट बैंक के पीछे - 32,कु. पूजा सेन / शिवनन्दन सेन गंजपारा , 56,शंकर शर्मा /शारदा शर्मा - 57,मोहम्मद जाकिर /मोहम्मद बशीर - 66,नेहा केसरवानी / रवि केसरवानी - 71,प्रहलाद लालवानी / गोविंद लाल - 72,अय्युब गहलोत / सिराजुद्दीन- 79,श्रीमती शीतल जांगीड़ /महेन्द्र जांगीड़ - 80,मुनव्वर अली / मुकद्दर अली - 83,जाकीर हुसैन / मुकद्दर अली - 84,नागेश्वर सोनकर - 89,गिरधारी देवांगन / खोदूराम - 93 बाजार विभाग द्वारा बताया कि अलग-अलग दुकानों पर अलग-अलग बकाया है। कई दुकानदारों को समय रहते नोटिस भेजे गए, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण दुकानों को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आयुक्त सुमित अग्रवाल की चेतावनी,नगर निगम ने चेताया है कि भविष्य में भी किराया न जमा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

## खबर-खास

### सर्चिंग पर गए जवान की मोटरसाइकल दुर्घटना में मौत

**गरियाबंद।** मंगलवार की सुबह पुलिस विभाग के लिए काफी दुख भरा रहा,जहां सर्चिंग पर गए एक जवान की मोटरसाइकल दुर्घटना मौत हो गई। घटना में मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार के सुबह सीआरपीएफ65 बटालियन के जवान सर्चिंग पर गए हुए थे उसी दौरान राजस्थान निवासी 57 वर्षीय जवान भंवरलाल मिणा की मोटरसाइकल छिन्दंला,आमामोरा,ओढ के बीच वे जिस मोटरसाइकिल से जा रहे थे वो अनियंत्रित होकर गहरे खाई में गिर गई,जिससे उक्त जवान को गहरी चोट लगी जिससे उनकी मौत हो गई।वही सर्चिंग पर निकले अन्य जवानों के द्वारा भंवर लाल मीणा को जिला अस्पताल लाया गया और मृतक का पोस्मार्टम कराया गया।इस घटना को लेकर पुलिस विभाग में शोक का लहर निर्मात हो गया है।

### थाना शोभा अंतर्गत ग्राम रक्शापथरा के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा डम्प किये 1 नग एके 47 एवं 12 बोर हथियार बरामद

**गरियाबंद।** डीजीएन डिवीजन द्वारा डम्प किये गये 1 नग एके 47 एवं 1 नग 12 बोर हथियार को बरामद किया गया।घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को गरियाबंद में आत्मसमर्पित माओवादियों के अनुसार डीजीएन डिवीजन द्वारा हथियार डम्प किये जाने की जानकारी व निशानदेही पर गरियाबंद से जिला पुलिस बल आप्स टीम ई-30 को 20 जनवरी को रवाना किया गया था। ई-30 टीम एवं बीडीएस की संयुक्त टीम द्वारा थाना शोभा के ग्राम रक्शापथरा जंगल क्षेत्र में सूचना की निशानदेही जगह का सर्च करने पर टेकरी के उपर चट्टान के किनारे नक्सलियों द्वारा डम्प कर रखे 1 नग एके 47, मय 1 नग खाली मैग्जीन एवं 1 नग 12 बोर हथियार को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

### पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ

**पाटन।** महिला बाल विकास विभाग, परियोजना पाटन में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ हेतु आज दिनांक 19/1/26 से 24/1/25 तक चार बैच में -पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती निशा सोनी उपाध्यक्ष नगर पंचायत पाटन की अध्यक्षता में तथा श्री लालेश्वर साहू अध्यक्ष साहू समाज पाटन ,श्रीमती अन्नपूर्णा जी पार्षद नगर पंचायत पाटन के आतिथ्य में हुआ, सरस्वती वंदना के साथ प्रशिक्षण आरंभ किया गया। उक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य 0 माह से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रारंभिक उद्दीपन एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना एवं स्वास्थ्य पोषण के साथ खेल खेल मे बेहतर शिक्षा देना है । इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के क्षमता वर्धन किया जाएगा,जिससे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मजबूत नींव का निर्माण किया जा सके। इस कार्यक्रम में परियोजना पाटन की परियोजना अधिकारी श्रीमती छाया वर्मा, पर्यवेक्षक नम्रता तिवारी, तिलोत्तमा मोटघरे, ममता साहू, उर्वशी देशलहरे, सुनीता पुसम, समता सिंग, मेघा मोहरिल, झरना दास, कंचन राठी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

### बेमेतरा जिले में 26 को शुष्क दिवस घोषित

**बेमेतरा।** गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी 2026 (सोमवार) को बेमेतरा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें एवं उनसे संलग्न अहाते पूर्णत: बंद रहेंगे। आदेशानुसार जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें-एफएल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) के साथ-साथ मद्य भण्डारण भाण्डागार तथा मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता) एवं एफएल.-1 (ख-अहाता) को भी 26 जनवरी को पूर्णत: बंद रखा जाएगा। इस दिन न तो मदिरा का विक्रय किया जाएगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरा संव्यवहार मान्य होगा। कलेक्टर ने संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

## गरियाबंद पुलिस एवं आरटीओ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लर्निंग लायसेंस बनाए जाने हेतु शिविर का आयोजन

### शिविर के पहले दिन 45 लोगो का लर्निंग लायसेंस बनाया गया

**गरियाबं।** गरियाबंद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत 19 जनवरी को पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धिरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में एसडीओपी ओम प्रकाश कुजुर व लितेश सिंह उप पुलिस अधीक्षक नोडल यातायात एवं यातायात टीम जिला परिवाहन अधिकारी रविन्द्र ठाकुर के द्वारा थाना मैनपुर क्षेत्र में जिला परिवहन विभाग से समन्वय कर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम व लर्निंग लायसेंसे शिविर का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय आयोजित शिविर के पहले दिन 45 लोगो का लर्निंग लायसेंस बनाया गया।

शिविर में लर्निंग लाइसेंस के साथ-साथ वाहन चालको को सड़कों पर आवश्यक रूप से यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।साथ ही परिवहन पुलिस विभाग से यातायात प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक रामाधार मरकाम,प्र.आर.धर्मेन्द्र ठाकुर, आरक्षक विरेन्द्र पटेल,अनिल पाण्डेय,जिला परिवहन विभाग से टीम उपस्थित रहे।

# तेलघानी बोर्ड की पहल से प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, स्व-सहायता समूह होंगे आत्मनिर्भर-जितेंद्र कुमार साहू

### तेलघानी बोर्ड से प्रदेश में कृषि एवं रोजगार को नया आयाम - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की प्रोत्साहन नीति से किसान, महिला समूह और युवा लाभान्वित होंगे

**बेमेतरा।** छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार साहू की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की ग्रामीण आजीविका, फसल विविधीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता पदमाकर, कृषि, उद्यानिकी, उद्योग, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एन.आर.एल.एम) विभाग और जिला अभिहित अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा किसानों को धान के बजाय तिलहन एवं अन्य विविध फसलें उगाने पर प्रोत्साहन राशि का विस्तार किया गया है, जिससे तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके तहत पंजीकृत किसानों को पंजीकृत धान के रकबे को तिलहन फसल में बदलने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि किसान धान की परंपरागत खेती के साथ फसल विविधीकरण को अपनाकर आय बढ़ा सकें। वर्तमान में राज्य सरकार ने कृषि कल्याण के मद में यह नीति अमल में लाई है, जिससे किसानों की आमदनी और खाद्यान्न के साथ तेल उत्पादन में भी सुधार संभव हो सकेगा।

### तेलघानी यूनिट से महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण

अध्यक्ष श्री साहू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि तेलघानी बोर्ड की महत्वपूर्ण पहल के अन्तर्गत स्व-सहायता महिला समूहों को तेल मिल इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर तेल का उत्पादन होगा और ग्रामीण महिला समुदाय की आर्थिकता में वृद्धि होगी। यह पहल प्रदेश भर में स्वावलंबी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाएगी तथा पारंपरिक आजीविका को आधुनिक स्वरूप देगी। एस.एच.जी. समूहों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और विपणन नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे उत्पादित तेल का विपणन स्थानीय एवं राज्य स्तर पर संभव हो सके।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि युवाओं को उद्योग और तेल प्रसंस्करण से जुड़े कौशल में प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के साथ ही युवाओं को अपनी भूमि और संसाधनों से जुड़कर काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को निर्देश दिए गए कि तिलहन फसलों-जैसे सरसों, तिल, मूंगफली आदिके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे।

# सामाजिक समरसता और लचीलापन मनवा कुर्मी समाज की पहचान - विजय बघेल

### डॉ एस एन मढ़रिया , पर्यावरण कार्यकर्ता रोमशंकर सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित

**दुर्ग।** मुख्य अतिथि विजय बघेल सांसद दुर्ग ने मनवा कुर्मी क्षत्रीय समाज में सामाजिक समरसता और लचीलापन मनवा कुर्मी समाज की पहचान है उक्ताशय के उदगार सांसद विजय बघेल ने मनवा कुर्मी क्षत्रीय समाज नगर इकाई दुर्ग के वार्षिक अधिवेशन शंकर नगर स्थित छात्रावास भवन में मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसी के कारण समाज में कई कई रूढ़िवादी परंपराएं हटाई जा सकी है, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के लोगों के योगदान को भी इस मौके पर याद किया साथ ही नगर इकाई की मांग पर उन्होंने डोमशेड निर्माण कार्य हेतु यथा संभव राशि की अनुशंसा का आश्वासन दिया। विशेष अतिथि डॉ एस एन मढ़रिया न्यूरोसर्जन ने अपने चिकित्सकीय जीवन को बड़ों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा का प्रतिफल बताया। उन्होंने दुर्ग शहर में समाज की एक जुटता की प्रशंसा की।कार्यक्रम के अध्यक्ष ईश्वरी वर्मा राज प्रधान दुर्ग ने खचाखच भरे हॉल को देख कर इकाई की सक्रियता की प्रशंसा की, उन्होंने समाज के ऐसे परिवारों को जो सामाजिक गतिविधियों से दूर रहते हैं उन्हें अभियान चला कर सक्रिय करने तथा वार्षिक शुल्क जमा कराने पर बल दिया। नगर इकाई अध्यक्ष रोशन वर्मा ने स्वागत भाषण व वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वहीं छात्रावास समिति का प्रतिवेदन धरम वर्मा ने प्रस्तुत किया एवं कोषाध्यक्ष ने आय व्यय की जानकारी दी इसके पहले कार्यक्रम क प्रथम सत्र में बच्चो तथा महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियों दी एवं खेलकूद प्रतियोगिता हुआ। समाज द्वारा वर्ष 2026 का मनवा श्री शिखर सम्मान ग्राम लिमतरा निवासी डॉ सत्य नारायण मढरिया को प्रदान किया गया। डॉ मढरिया छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के न्यूरोसर्जन हैं। वे अब तक 15000 से अधिक न्यूरोसर्जरी कर चुके हैं साथ ही इंडियन मेडिकल काउंसिल के सदस्य भी हैं वहीं विशिष्ट सम्मान अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता व पत्रकार रोमशंकर यादव, निरंतर समाज सेवा हेतु श्रीमती अन्नपूर्णा मढ़रिया, पेंशनरों के हित में कार्य करने के लिए भूपेंद्र कुमार वर्मा तथा एससी, एसटी,ओबीसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल वर्मा को इन वर्गों के बीच कार्य करने के लिए विशेष सम्मान दिया गया। साथ पीएससी 2025 में चयनित प्रतिभाओं स्वप्निल वर्मा, सुनील कुमार कश्यप, टेसूकांत वर्मा,सागर वर्मा, साक्षी वर्मा तथा प्रभा कश्यप का शाल श्रीफल तथा स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।

समाज द्वारा संचालित छात्रावास भवन में रहकर पढ़ाई पूरी कर शासकीय सेवा से जुड़े युवकों ,दुर्ग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर जाकर गतिविधियों की जानकारी देने तथा सदस्यता अभियान पूरी करने योगदान देने वाले क्षेत्र प्रधानों का भी सम्मान किया गया।

# 400 किमी का सफर तय कर उदंती-सीतानदी पहुँचा बीमार गिद्ध, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

**गरियाबंद।** उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और सराहनीय सफलता सामने आई है। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंचे एक बीमार गिद्ध का उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व की टीम द्वारा सफल रेस्क्यू किया गया है। इससे पहले ओडिशा से आए बीमार हाथियों के इलाज के बाद अब महाराष्ट्र से आए बीमार गिद्ध का सुरक्षित रेस्क्यू और उपचार की पहल वन विभाग की सतर्कता को दर्शाती है।

मंगलवार सुबह करीब 11 बजे इन्दागांव (बफ़र) परिक्षेत्र के काण्डसर बीट में नियमित फुट पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलिंग श्रमिक राधेश्याम यादव ने एक गिद्ध को बीमार अवस्था में देखा।गिद्ध उड़ने में असमर्थ था और गर्दन झुकाकर जमीन पर बैठा हुआ था।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राधेश्याम यादव ने तत्काल परिक्षेत्र अधिकारी सुशील कुमार सागर को सूचना दी,जिसके बाद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।रेस्क्यू के दौरान पाया गया कि यह वाइट रंप्ड वल्चर है, जिसकी पीठ पर माइक्रो ट्रांसमीटर और जीपीएस लगा हुआ था।जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गिद्ध ने महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व से उड़ान भरी थी। प्रारंभिक तौर पर उसकी तबीयत खराब होने का कारण डी-हाइड्रेशन या बीमारी माना जा रहा है। बिलासपुर के वल्चर एक्सपर्ट अभिजीत शर्मा ने टेलीफोनिक कांप्रेंसिंग के माध्यम से उदंतीसीतानदी टाइगर रिज़र्व की टीम को सुरक्षित रेस्क्यू के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।गिद्ध को मौके पर पानी और आर्टिफिशियल फीड उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद उसे घने जंगल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बीट गार्ड रामकृष्ण साहू के माध्यम से गिद्ध को गरियाबंद लाया गया।

जंगल सफारी की डॉक्टर टीम से डॉ.जडिया एवं सुश्री ऋचा गरियाबंद पहुंचीं,जहां गिद्ध को रेस्क्यू केज में शिफ्ट किया गया। इसके पश्चात उसे उपचार के लिए नया रायपुर स्थित जंगल सफारी ले जाया जा रहा है। उपचार पूर्ण होने के बाद गिद्ध को पुनः सुरक्षित प्राकृतिक रहवास में छोड़ा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी वनों से आच्छादित है।ओढ़ङ्कआमामोरा की पहाड़ियों में पूर्व में भी गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्दागांव परिक्षेत्र की टीम एवं जंगल सफारी की डॉक्टर टीम का अहम योगदान रहा।यह रेस्क्यू अभियान माननीय वन मंत्री केदार कश्यप,पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ अरुण पाण्डेय तथा उदंतीङ्कसीतानदी टाइगर रिज़र्व की फील्ड डायरेक्टर सतोविशा समाजदार, उपनिदेशक एवं डीएफओ जंगल सफारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

# जनदर्शन के आवेदनों को संवेदनशीलता और गंभीरता से निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश

**सारंगढ़ बिलाईगढ।** कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मंगलवार की शाम को जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जनशिकायत पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों के निराकरण का समीक्षा किया और कहा कि, सभी अधिकारी संवेदनशीलता और गंभीरता से आवेदन का निराकरण करें। उन्होंने जल संसाधन विभाग में भू अर्जन के प्रकरणों में राज्य शासन को भेजे गए पत्र की सूचना आदि हितग्राहियों को भी उपलब्ध कराये ताकि उन्हें शासन के कार्य में पारदर्शिता का विश्वास बना रहे। कलेक्टर ने कहा कि, जिले में किसी भी अधिकारी कर्मचारी से जुड़े अनुकम्पा नियुक्ति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान का प्रकरण हो, वे गठित कमेटी के माध्यम से निराकरण करेंगे। कलेक्टर ने श्मशान घाट, खेल मैदान जैसे शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा हटाने के निर्देश दिए, वहीं ग्राम भेड़वन के आयुर्वेद हॉस्पिटल में पंचकर्म के सेटअप निर्माण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डॉ कन्नौजे ने ईऑफिस में सभी विभागों को निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक में आयोजित विभिन्न बैठकों के पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सयुंक्त खाता प्रकरण के निराकरण के लिए सहकारिता विभाग को निर्देश दिए।

कलेक्टर ने धान खरीदी के उड़न दस्ता टीम के सभी ज़ोनल जिला स्तरीय अधिकारियों को पूछा कि, कहाँ कहाँ किस किस धान खरीदी केंद्र का अवलोकन किये, वहां नोडल अधिकारी पटवारी उपस्थित थे या नहीं, कितने अपात्र धान को रिजेक्ट किये, कितने सही पाए इत्यादि बिन्दुओ पर आगामी धान खरीदी के अंतिम दिनों तक जांच करें। धान उपार्जन केन्द्र में जाकर स्टॉक का मिलान करें। सभी क्षेत्रों में अवैध धान भंडारण, परिवहन करने वाले कोचियों पर कार्यवाही करें। आगामी 26 जनवरी समारोह की तैयारी, पीएम आवास निर्माण, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदना, जिला अस्पताल निर्माण, संयुक्त जिला कार्यालय, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, पीएमश्री स्कूल निर्माण, अपार आईडी, सरस्वती सायकल वितरण, आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आश्रम छात्रावास के बालक बालिकाओं के हेल्थ चेकअप, एनीमिया जांच, विभिन्न विकास प्राधिकरणों के प्रगति कार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पीएम किसान सम्मान निधि राजस्व कार्य नक्शा बंटाकन, फौती नामांतरण, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी की संख्या बढ़ाने, पेंशनर रिपोर्ट, पेंशनरों के बैंक खाता से मोबाइल नंबर सीडिंग आदि के कार्यों का समीक्षा कर कलेक्टर ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

# गिरीश शर्मा शिक्षक साहित्य साधक सम्मान से सम्मानित

### राजिम में संस्कृति मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ सम्मान समारोह

**गरियाबंद।** शिक्षक साहित्य परिषद छत्तीसगढ़ के तत्वावधान आज सम्मान समारोह का आयोजन प्रेमरत्न मैरिज पैलेस राजिम किया गया,इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला खट्टी में पदस्थ सहायक शिक्षक गिरीश शर्मा को साहित्य शिक्षक साधक सम्मान से सम्मानित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल थे,कार्यक्रम की अध्यक्षता चंदू लाल साहू अध्यक्ष राज्य भंडार गृह निगम ने किया एवं विशेष अतिथि के रूप में रोहित साहू विधायक राजिम विधानसभा,संतोष उपाध्याय पूर्व विधायक,महेश यादव अध्यक्ष नगर पालिका राजिम,विभा अवस्थी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा एवं वरिष्ठ साहित्यकार विनय कुमार पाठक,मीर अली मीर उपस्थित थे।

राजिम के प्रेम रतन मैरिज पैलेस में शिक्षक साहित्य परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा किए गए इस आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,केरल,गुजरात,पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु, उत्तराखंड आदि राज्य के साहित्य कार सम्मिलित हुए जिन्हें समारोह में सम्मानित किया गया साथ ही इस अवसर पर गिरीश शर्मा सहित 31 शिक्षको को शिक्षक साहित्य साधक सम्मान से सम्मानित किया गया।आयोजित समारोह में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) राजिम विशाल महाराणा,जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर,तहसीलदार मयंक अग्रवाल,सहायक सांख्यिकिय अधिकारी श्याम चंद्राकर,ललित मिश्र,विवेक शर्मा,मुन्ना लाल देवदास,सागर शर्मा,पुरन लाल साहू,अनिल अवस्थी,ज्ञानेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित थे।इससे पूर्व भी गिरीश शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण,कोविड काल में आनलाईन क्लास एवं मोहल्ला क्लास के लिए राज्य स्तरीय सम्मान,जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान,इंदौर में भारत श्री सम्मान, अयोध्या में स्वदेश गौरव सम्मान,भोपाल में भारत भूषण सम्मान,मंच संचालन के लिए गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जा चुका है।शिक्षक साहित्य साधक सम्मान से सम्मानित किये जाने पर गिरीश शर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी जगजीत सिंह धीर,जिला मिशन समन्वयक शिवेश शुक्ला,सहायक परियोजना अधिकारी बुद्ध विलास सिंह,सहायक सांख्यिकिय अधिकारी श्याम चंद्राकर,कृपाल पैकरा,मनोज केला,विकासखंड शिक्षा अधिकारी गजेंद्र ध्रुव, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक छन्नूलाल सिन्हा, संकुल समन्वयक दल प्रसाद साहू,संजीव साहू, परमेश्वर,निर्मलकर,नितिन बखारिया,होरी लाल साहू,देवेन्द्र पांडे,दीपक सरवैया आदि बधाइ दी।

# टैरिफ के बावजूद वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर छू सकती है नई ऊचाईयां

प्रहलाद सबनानी

**वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है।**

दिनांक 1 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के आर्थिक विकास से सबंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़े 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए है। इस अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सकल घरेलू उत्पाद से सम्बंधित प्रथम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विकास से सम्बंधित द्वितीय अग्रिम अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का ही है परंतु भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग का अनुमान 7.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का है। भारत की आर्थिक विकास दर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक रहने की सम्भावना विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक (7.2 प्रतिशत), फिच नामक रेटिंग संस्थान (7.4 प्रतिशत) आदि संस्थानों ने भी व्यक्त की है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में हासिल की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के कुछ मुख्य कारणों में शामिल हैं - (1) केंद्र सरकार के स्थिर उपभोग खर्च में वृद्धि दर जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.3 प्रतिशत की रही थी, वह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (2) विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.5 प्रतिशत की रही थी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है; (3) सकल मान योग में वृद्धि दर का 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है; (4) सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है; (5) सेवा एवं कृषि क्षेत्र में क्रमशः 9.1 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की सम्भावना व्यक्त की गई है; (6) भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर का 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना होना भी शामिल है। अप्रेल 2025 से नवम्बर 2025 के खंडकाल में राजकोषीय घाटा 9.8 लाख करोड़ का रहा है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमान का 62.3 प्रतिशत है, अतः बजटीय घाटा भी अभी तक नियंत्रण में ही रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़ रहने

का अनुमान लगाया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होगा। इस प्रकार केंद्र सरकार की आय एवं व्यय से सबंधित स्थिति भी पूर्णतः नियंत्रण में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को उत्साहवर्धक माना जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्धि दर ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बावजूद रहने वाली है। दरअसल ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ को वित्तीय बाजार में बहुत गम्भीरता से लिया जाकर इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। परंतु, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास दर पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिका को भारत से होने वाले निर्यात की कम मात्रा भी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को 7,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हुए थे, जबकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा था। अतः भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.85 प्रतिशत ही रहे हैं। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है ही नहीं (चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, इसीलिए चीन पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव अधिक हो सकता है), भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक उपभोग पर आधारित है। यदि भारत के नागरिक स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक सेवन करते हैं तो ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को शून्य भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी भारतीय समाज को लगातार प्रेरणा दी जा रही है कि वे भारत में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें ताकि भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संघ ने पंच परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है, जिसमें पांच बिंदु शामिल किए गए हैं - स्वदेशी का उपयोग, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन। भारत में समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इन संस्कारों में भारत के नागरिकों में ह्रदेश प्रथमह्र के भाव का जागरण भी शामिल है। लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता नागरिकों की भागीदारी और कर्तव्यों के प्रति सजगता पर निर्भर करती हैं। जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देश की प्रगति होती हैं। समाज की प्रगति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता तथा कटिबद्धत्ता आवश्यक है। करों का समय पर और सही राशि का भुगतान करना नागरिकों का कर्तव्य है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए करों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसी सामाजिक सेवाओं में भाग लें।

किसी भी देश के नागरिक यदि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना प्रारम्भ करते हैं तो इससे देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात कम होता है और देश में ही रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करना है परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है क्योंकि आज विश्व के समस्त देश एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गए हैं, जिसके चलते उत्पादों का एक देश से दूसरे देश में आयात एवं निर्यात बहुत आसान बन पड़ा है। आचार्य श्री विनोबा भावे जी कहते हैं स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। संघ ने इसमें एक बिंदु जोड़ दियाः आत्मनिर्भरता, अहिंसा और सादगी। प्रत्येक भारतीय नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह मितव्ययिता से जिए ताकि संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जा सके। परंतु, इसका आश्य कंजूसी करना कदापि नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों के साथ ही केंद्र सरकार ने भी आर्थिक क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं जिसके चलते हाल ही के समय में भारत की आर्थिक विकास दर में वृद्धि दर में लगातार सुधार दिखाई दिया है। विशेष रूप से ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ के प्रभाव को लगभग शून्य करने के उद्देश्य से भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इनमे विशेष रूप से शामिल हैं यूनाइटेड किंगडम, ओमान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि। यूरोपीयन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न होने जा रहा है। सम्भवत 27 जनवरी 2026 को इस मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीयन यूनियन एवं भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित होने वाले उत्पादों के लिए भारत ने अन्य देशों के रूप में बाजार तलाश लिए हैं एवं इन देशों को विभिन्न उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ हो चुका है जिससे नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। वैसे, भारत और अमेरिका के बीच भी मुक्त व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं शीघ्र ही इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद तो भारतीय उत्पादों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत को भी कम अथवा समाप्त किया जा सकता है, इससे अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका को भी भारत से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में और अधिक वृद्धि हासिल की जा सकेगी।

## संपादकीय

### बंगाल 'महाजंगलराज' नहीं

बेशक करीब 6800 कंपनियों और लघु उद्योगों ने अपने दफ्तर, कारखाने, ढांचे आदि पश्चिम बंगाल से खत्म किए हैं और महाराष्ट्र, गुजरात में स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मौजूदा कार्यकाल में ही करीब 2300 कंपनियों ने बंगाल को छोड़ा है। यह औद्योगिक विकास की नकारात्मक स्थिति है, लेकिन इसके समानांतर का यथार्थ यह भी है कि आईटी, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में इन्फोसिस सरीखी वैश्विक कंपनी कोलकाता में अपना औद्योगिक तंबू गाड़ रही है। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह रिलायंस ने बंगाल में निवेश की घोषणा की है। सीमेंट और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों की कंपनियां बंगाल में अपने ढांचे स्थापित कर रही हैं। बेशक 2006-08 के दौर में बंगाल के सिंगूर इलाके में टाटा समूह को 'नैनो कार' का संयंत्र उठाना पड़ा और वह गुजरात के साणंद में पुनःस्थापित किया गया। यह राजनीतिक युद्ध का विवाद बना और सर्वोच्च अदालत के दखल से किसानों की करीब 1000 एकड़ जमीन वापस करनी पड़ी। दुर्भाग्य और विडंबना है कि उसमें से करीब 300 एकड़ जमीन पर ही खेती हो पा रही है। ऐसे परिदृश्य में दुष्प्रचार किया जाता रहा है कि पश्चिम बंगाल 'उद्योगहीन' राज्य है। यह तथ्यहीन प्रचार है, क्योंकि बंगाल देश की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी औसत विकास दर करीब 12 फीसदी है। यह राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बंगाल का योगदान 6.15 फीसदी है। हालांकि यह योगदान कभी 10 फीसदी से अधिक होता था। पश्चिम बंगाल की गिनती गरीब राज्यों में की जाती है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से भी कम है। हालांकि राज्य की जीडीपी 20.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और 2030 तक 400 अरब अमरीकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। बंगाल में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। चावल, चाय, कपड़ा, जूट, कोयला, लौह और आईटी उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था एक मिश्रित, सामाजिक बाजार की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पर 'महाजंगलराज' का गंभीर आरोप चस्पा किया है। यह भी जनता को बताया है कि 100 घरों में से औसतन 4 घरों में ही 'नल का जल' है, जबकि यह हकीकत नहीं है। प्रधानमंत्री की 'नल से जल' योजना की शोधपरक रपट सार्वजनिक की जाए, तो ढेरों छिद्र सामने आएंगे और योजना के भ्रष्ट आचरण की कलई खुलेगी। बहरहाल आज विषय यह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार, 18 जनवरी को बंगाल में चुनावी शंखनाद की शुरूआत की है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को विदा करने का आह्वान किया है। बंगाल में कानून व्यवस्था के निकम्मेपन, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा, घुसपैठ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या सरीखे अवैध प्रवासियों का संरक्षण तथा वोट बैंक, भ्रष्टाचार आदि के हालात समझ में आते हैं।

## चिंतन-मनन

### क्या है कृष्णकर्म?

ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो। कोई भले ही कितने ही कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में मस्त है, तो उसे इस व्यापार को कृष्णभावनामृत में परिणत करने के लिए, कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे, तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्णकर्म है। अपनी इंद्रियतृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर, वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कर सकता है। यह सब कृष्णकर्म है।

मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं होती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्णभावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण-मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्णकर्म है। मत्परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परमलक्ष्य, भगवान कृष्ण के परमधाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं।

## अमेरिका और विश्व में अलग-थलग पडे ट्रंप, गैंगस्टर की छवि?

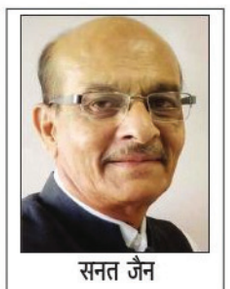

सनत जैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि सारी दुनिया में एक गैंगस्टर के रूप में बन रही है। जो अपनी सत्ता और ताकत के बल पर सारी दुनिया के देशों में कब्जा करना चाहते हैं। वह दादागिरी के बल पर शांति के मसीहा बनना चाहते हैं। ट्रंप को लगता है, उनके पास ईश्वरी शक्तियां आ गई हैं। वह जो चाहे वह कर सकते हैं। वह अमेरिका के संविधान में संशोधन कर तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में वह अपने परिवार के लोगों को सारी दुनिया के देशों में स्थापित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी नीतियों के कारण अमेरिका और विश्व में उनका विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर जो अभियान छेड़ा है, उसे लेकर यूरोपीय और अन्य देशों पर जिस तरह का टैरिफ लगाया गया है, उसके कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का दूसरा वर्ष शुरू हो गया है। जब से वह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं सारी दुनिया के देशों को टैरिफ के नाम पर वह धमका रहे हैं। दुनिया के 91 देशों के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ की तलवार लटका रखी है। अमेरिका में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ईरान में अमेरिका को कड़ा झटका लगा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का जिस तरह से अपहरण कर अमेरिका की जेल में बंद करके रखा गया है, उससे ट्रंप और अमेरिका की साख सारी दुनिया में गिर गई है। ग्रीनलैंड में कब्जे और यूक्रेन को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों को अपने निशाने पर लिया है, उसके बाद अमेरिका का विरोध यूरोप के देशों में बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के कारण ट्रंप अपने ही देश में अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। हाल ही में हुए सर्वे में 58 फीसदी अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप की नीतियों को अमेरिका के खिलाफ बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कई फेसलों पर अमेरिका की विभिन्न कोर्टों ने रोक लगा दी है। एजुकेशन, क्लीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांजैक्शन से जुड़ी सहायता को अमेरिका ने रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय विदेशी सहायता कार्यक्रम को रोक दिया है। यहां तक की वैश्विक संस्थाओं को अमेरिका द्वारा जो सहायता दी जा रही थी। उसको रोककर संस्थाओं से अलग होने की नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का विरोध सारी दुनिया के देशों में बढ़ता जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ, इमीग्रेशन, रक्षा और एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरह से यूरोपीय और नाटो देशों को नाराज किया है। इसका असर नवंबर माह में होने वाले मिड टर्म चुनाव में देखने को मिल सकता है। सर्वे के अनुसार ट्रंप संसद में अपना बहुमत खो सकते हैं। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है। ट्रंप मिड टर्म चुनाव को टाल भी सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय और नाटो देशों के साथ जिस तरह से टकराव पैदा कर रहे हैं। उसको देखते हुए आगामी महीने डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी उथल-पुथल वाले साबित हो सकते हैं। अमेरिका की अभी तक जो वैश्विक छवि बनी हुई थी, उसमें तेजी के साथ दरार बढ़ती चली जा रही है।

वैश्विक व्यापार संगठन की उपेक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डब्ल्यूएचओ और अन्य संस्थाओं से जिस तरह की दूरी डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। उससे स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप से जिन कारणों से युद्ध की शुरूआत हुई थी ठीक उसी तरह की स्थिति एक बार फिर बनना शुरू हो गई है। ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना भी बनने लगी है। इस बात की आशंका आर्थिक विशेषज्ञ जता रहे हैं। ट्रंप की वर्तमान नीतियों से अमेरिका ठीक उसी राह पर चल पड़ा है, जैसे कभी सोवियत रूस चला था। जिसके कारण सोवियत रूस का विघटन हुआ। अमेरिका का जो वैश्विक वर्चस्व था, उसको बड़े पैमाने पर चुनौती मिल रही है। इस चुनौती का सामना किस तरह ट्रंप और अमेरिका करेगा, इसके लिए समय का इंतजार करना होगा।

## बंगाल में लोकतंत्र, विकास और अस्मिता की निर्णायक परीक्षा-घड़ी

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां सत्ता, संघर्ष, कानून और जनभावना-चारों धाराएं एक-दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं। यह टकराव केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भर नहीं है, बल्कि यह उस शासन शैली, लोकतांत्रिक मयार्दा और विकास दृष्टि की भी परीक्षा है, जिसके आधार पर बंगाल अपनी आने वाली राजनीतिक दिशा तय करेगा। लंबे समय तक ह्रखेला होगाह्न के नारे के सहारे भाजपा को रोकने में सफल रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी नजर आ रही हैं। आज समूचे देश की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी है। वहां आगामी विधानसभा काफी रोमांचक एवं निर्णायक होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल का नया भविष्य बुनने की दिशाएं उद्घाटित होगी।

एक ओर केंद्र और राज्य के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, अदालती टिप्पणियां और कानूनी बहसें राजनीतिक विमर्श को नियंत्रित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने केवल एक कानूनी प्रश्न ही नहीं उठाया, बल्कि यह संकेत भी दिया कि राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप की सीमाएं कहां तक हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की उस राजनीतिक छवि को आंशिक रूप से प्रभावित किया है, जो अब तक स्वयं को केंद्र के कथित दमन के विरुद्ध संघीय ढांचे की रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही हैं। अदालतों में लंबी चलने वाली कानूनी लड़ाइयों का राजनीतिक प्रभाव तुरंत और गहरा होता है, विशेषकर तब, जब चुनाव नजदीक हों और जनता का ध्यान प्रशासनिक उपलब्धियों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप पर केंद्रित होने लगे। बंगाल की राजनीति की एक विशिष्ट विशेषता यह रही है कि यहां विचारधारा और भावनाएं अत्यंत तीव्र रूप से अभिव्यक्त होती हैं। वाम मोर्चे के लंबे शासन के बाद ममता बनर्जी का उदय एक जनांदोलन के रूप में हुआ था। उन्होंने न केवल वामपंथी वर्चस्व को तोड़ा, बल्कि खुद को गरीब, हाशिए के वर्ग और क्षेत्रीय अस्मिता की आवाज के रूप में स्थापित किया। शुरूआती वर्षों में उनकी सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाओं और सशक्त राजनीतिक संप्रेषण के माध्यम से जनता का विश्वास भी अर्जित किया। किंतु समय के साथ सत्ता का केंद्रीकरण, संगठन पर अत्यधिक नियंत्रण और विरोध के प्रति असहिष्णुता जैसे आरोप भी समानांतर रूप से उभरते गए।

भाजपा ने इन्हीं कमजोरियों को अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक भाजपा ने बंगाल में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद तथा भ्रष्टाचार विरोधी विमर्श को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से वापसी की, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा बंगाल की राजनीति में एक स्थायी और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। मत प्रतिशत में अंतर और सीटों का आंकड़ा भाजपा के लिए भले ही निराशाजनक रहा हो, पर संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक आधार का विस्तार उसके लिए भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोलता है। हाल के वर्षों में बंगाल में विकास का प्रश्न अपेक्षाकृत पीछे छूटता दिखाई दिया है। उद्योग, निवेश और रोजगार के मुद्दे राजनीतिक शोर में दब गए हैं। आम जनता की एक बड़ी चिंता यह भी है कि राज्य की राजनीति निरंतर टकराव और हिंसा के आरोपों से क्यों घिरी रहती है। चुनावी हिंसा, राजनीतिक कार्यकताओं पर हमले और प्रशासन की निष्पक्षता पर उठते सवाल राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पड़ोसी देशों से अवैध घुसपैठ, सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव और कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। इन मुद्दों पर ममता सरकार का रुख अक्सर रक्षात्मक दिखाई देता है, जबकि भाजपा इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर व्यापक समर्थन जुटाने का प्रयास करती है।

महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनावों और बिहार में भाजपा को मिली हालिया सफलता ने पार्टी के आत्मविश्वास को निश्चित रूप से बढ़ाया है। भाजपा का यह विश्वास कि बंगाल अब भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार है, केवल चुनावी आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह इसे एक लंबी रणनीति का हिस्सा मानती है। किंतु बंगाल कोई साधारण राजनीतिक मैदान नहीं है। यहां की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृति किसी भी दल के लिए आसान नहीं रही है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत आज भी उनकी जमीनी पकड़ और भावनात्मक अपील है, जो उन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अलग, एक क्षेत्रीय और स्थानीय नेता के रूप में स्थापित करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव वास्तव में इस बात की कसौटी होंगे कि जनता विकास, स्थिरता और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देती है या फिर भावनात्मक और पहचान आधारित राजनीति को? क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटकर यह सिद्ध कर पाएंगी कि केंद्र से टकराव ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, या भाजपा जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल होगी कि परिवर्तन ही स्थायित्व और विकास का रास्ता है, यह प्रश्न अभी खुला हुआ है। अदालती प्रक्रियाएं, राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बंगाल की जनता के हाथ में है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति आज संकीर्णता और सांप्रदायिक ध्रूवीकरण के ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसने विकास की गति को गंभीर रूप से अवरुद्ध किया है। कभी देश की आर्थिक, औद्योगिक और बौद्धिक राजधानी कहलाने वाला बंगाल-विशेषकर कोलकाता, आज निवेश, उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। ममता बनर्जी के लंबे शासनकाल में औद्योगिक विश्वास का क्षरण, पूंजी पलायन, बंद होती इकाइयाँ और युवाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन इस गिरावट के स्पष्ट संकेत हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठते प्रश्न, विपक्षी आवाजों का दमन और चुनावी हिंसा की घटनाएँ राज्य के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट करती हैं। इसके साथ ही, राज्य में सामाजिक ताने-बाने को लेकर बढ़ती आशंकाएँ भी कम चिंताजनक नहीं हैं। अनेक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक संबंधों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं; विशेषकर हिंदू समाज के एक हिस्से में असुरक्षा की भावना ने जनमन को आहत किया है। इन घटनाओं और धारणाओं ने जनता के भरोसे को कमजोर किया है और शासन के प्रति निराशा को बढ़ाया है। राजनीति जब पहचान और विभाजन के इर्द-गिर्द सिमटती है, तो विकास, समावेशन और सामाजिक सौहार्द पीछे छूट जाते हैं, यही आज के बंगाल की त्रासदी बनती दिख रही है।

ऐसे समय में बंगाल की जनता के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग होना अनिवार्य है। यह राज्य केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता उसकी बौद्धिक परंपरा, भावनात्मक संवेदनशीलता, धार्मिक सहअस्तित्व, आध्यात्मिक खोज और समृद्ध साहित्यिक विरासत से निर्मित है-रवींद्रनाथ से विवेकानंद तक की धरोहर इसे दिशा देती रही है। दंगों, हिंसा और भय के साए में इस अस्मिता पर जो दाग लगे हैं, उन्हें मिटाने का मार्ग शांतिपूर्ण, जागरूक और निर्भीक लोकतांत्रिक सहभागिता से ही निकलेगा। आगामी चुनाव जनता के लिए आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का अवसर हैं-जहाँ मत केवल सत्ता नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य, उसकी संस्कृति और उसके लोकतांत्रिक आत्मसम्मान की रक्षा का माध्यम बनना चाहिए। बंगाल की बनती नई तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह तस्वीर संघर्ष और संभावनाओं, आशंकाओं और उम्मीदों से बनी है। एक ओर सत्ता का अनुभव और जनाधार है, तो दूसरी ओर आक्रामक विपक्ष और राष्ट्रीय राजनीति की ताकत। लोकतंत्र की यही खूबी है कि वह अंतिम शब्द जनता को देता है। बंगाल के मतदाता ही तय करेंगे कि शह-मात की इस राजनीति में अगली चाल किसकी होगी और कौन-सा पक्ष अंततः बाजी मारेगा।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

# खबर-खास

## छात्रों से मारपीट के आरोप में शिक्षिका सस्पेंड, शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई

**बिलासपुर।** शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरारी में छात्रों के साथ मारपीट के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित महिला शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक (जेडी) द्वारा की गई है। मामला बिल्हा विकासखंड से जुड़ा है।

मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल में पदस्थ शिक्षिका विजय लक्ष्मी गुप्ता पर छात्रों को प्लास्टिक और लोहे के पाइप से पीटने के गंभीर आरोप लगे थे। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच के दौरान शिक्षिका ने भी बच्चों की पिटाई करने की बात स्वीकार की।

डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित करने के आदेश जारी किए। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है।

विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि स्कूलों में बच्चों का सुरक्षित और अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

## विभिन्न विकास कार्यों हेतु 49.95 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

**दुर्ग।** कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 49.95 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र विधायक गजेंद्र यादव द्वारा अनुशंसित इन कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-दुर्ग द्वारा किया जाएगा।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत कार्यों में वार्ड क्रमांक 23 दीपक नगर में हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु, सामुदायिक भवन के पास अहाता एवं मंच निर्माण हेतु तथा मंदिर के पास डोमशेड निर्माण प्रत्येक कार्य हेतु 9 लाख 99 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, वार्ड क्रमांक 44 बाबा गुरुघासीदास वार्ड के फोकट पारा स्थित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा इसी क्षेत्र के रसोई कक्ष, शौचालय एवं पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य हेतु प्रत्येक कार्य के लिए 9 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

## रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में 52 युवाओं का हुआ चयन

**दुर्ग।** राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) भिलाई में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का सफल आयोजन किया गया। मेले में 130 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से साक्षात्कार उपरांत 52 अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के लिए चयन किया गया। यह मेला प्रत्येक तीन माह में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) आर. बी. तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। संस्था के प्राचार्य टी. के. सातपुते ने अप्रेंटिसशिप के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया एवं करियर निर्माण की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को इसे उद्योग में प्रवेश का सशक्त माध्यम बताते हुए राज्य एवं राज्य से बाहर की कंपनियों में कार्यग्रहण हेतु प्रेरित किया। मेले में भिलाई एवं आसपास की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों ने भाग लेकर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, फाउंड्रीमैन एवं कोपा जैसे विभिन्न ट्रेड्स के लिए चयन किया। उद्योग प्रतिनिधियों ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे युवाओं और उद्योगों के बीच मजबूत सेतु बताया।

## पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समय पर निराकरण नहीं होने पर होगी कार्रवाई - कलेक्टर

**कोरिया।** कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन तथा कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की विभागवार स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से सवाल-जवाब किए और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए, लापरवाही अथवा हीलाहवाली पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर त्रिपाठी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले में सुपोषण के स्तर में सुधार हेतु विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जा रहे 'कोरिया मोदक' पौष्टिक लड्डू के वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि कम वजन वाले शिशुओं की जन्मदर को कम करने के लिए यह नवाचार महत्वपूर्ण है, अतः महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एनआरएलएम द्वारा सतत निगरानी कर व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों को प्रदर्शनी की तैयारियाँ शीघ्र पूर्ण करने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल समय पर कराने के निर्देश दिए।

# सात माह से वेतन नहीं, हड़ताल पर उतरे 92 सफाई कर्मचारी, आश्वासन के बाद टूटी हड़ताल



**राजनांदगांव।** नगर निगम में बम्बे ठेकेदार के अधीन कार्यरत 92 सफाई कर्मचारियों ने 7 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए हड़ताल शुरू कर दिया। इन कर्मचारियों का ठेकेदार द्वारा लगभग तीन वर्ष की इपीएफराशि भी जमा नहीं की गई है। जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों में अक्रोश है।

वही 3 साल से इपीटफ भी जमा नहीं किया गया है। इधर कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किए जाने की सूचना मिलने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले भी निगम पहुंचे इस दौरान उन्होंने कहा कि कलेक्टर दर से कम रेट में निगम के ठेका कर्मचारियों को कम दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सात माह से इन कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर पा रही है, यह दुर्भाग्य जनक है। उन्होंने कहा कि हमने आयुक्त से बात की है। आयुक्त ने तीन माह का वेतन डालने का आश्वासन दिया है।

सफाई कर्मचारियों को 7 में से 3 माह का वेतन डालने और मार्च माह तक इपीएफ की राशि जमा किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों ने अपना हड़ताल समाप्त किया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि हड़ताल पर चले जाना व्यावहारिक नहीं। समस्या को लेकर पहले बातचीत किया जाना था। वही उन्होंने कहा कि हमने ठेकेदार को 17 महीने का भुगतान किया है फिर भी ठेकेदार के द्वारा ईपीएफ जमा नहीं किया गया है।

# कलेक्टर ने उड़नदस्ता टीम को सभी चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी रखने के दिए

**जशपुर।** कलेक्टर रोहित व्यास ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली और आगामी 24 और 25 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आगमन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कोतबा, मयाली में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री कोतबा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन और आम सभा को भी सम्बोधित करेंगे इसी प्रकार कुनकुरी विकास खंड के मयाली में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए लोकार्पण भूमिपूजन की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और कार्यक्रम की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सभी एसडीएम जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को छुटे हुए सभी व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग को सरस्वती सायकल योजना के तहत छात्राओं को योजना का लाभ देने के लिए कहा है।

कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को पात्र दिव्यांग व्यक्तियों का यूडीआईडी नम्बर जनरेटर करके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी दिव्यांग छुटने न पाए इसका विशेष ध्यान रखें।

उन्होंने कहा दिव्यांग जनों का पेंशन राशन और शासन की योजना का लाभ देने के लिए कहा है। कलेक्टर ने पेंशन धारी हितग्राहियों का आधार अपडेट करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली।

# कचरे से खाद बनाने 29.50 लाख रुपए ज्यादा में दिया ठेका और वसूली राशि 9.27 लाख रुपए घटा दिए

### ठेकेदार को लाभ पहुंचाने बड़ी गड़बड़ी की आशंका

**भिलाई।** स्वच्छ भारत मिशन पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना कचरे से खाद बनाने के लिए बड़ी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। आशंका जताई जारही है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा खेल खेला गया है। जिसकी वजह से नगर निगम को बड़ी हानि हुई है। जबकि चौकाने वाली बात यह है कि कचरे से खाद बनाने के लिए निगम ने ठेकेदार को 5.77 करोड़ रुपए में ठेका दिया था, उसी काम को शासन के आदेश पर अब निगम ने ही 2.66 करोड़ में दिया है। मतलब निगम ठेकेदार को 3.15 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट किया है।

सेग्रीगेशन प्लांट में कचरे से खाद बनाने के लिए ठेका किया गया। तब ठेकेदार को लाभ पहुंचाने एक ओर जहां 29.50 लाख रुपए अधिक रेट में ठेका दिया गया। वहीं दूसरी ओर खाद के एवज में ठेकेदार से निगम जो राशि कटौती करता है, उस राशि को 9.27 लाख कम कर दिया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को 38.77 लाख रुपए वा??र्षिक लाभ पहुंचा गया और निगम को आ?र्थिक क्षति पहुंचाई गई है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज के आधार पर नगर निगम? भिलाई के पास शहर में 9 एसएलआरएम सेंटर है। जिसका पहला टेंडर 2 फरवरी 2023 को जारी किया गया। टेंडर में किसी एजेंसी ने भाग नहीं लिया। तब ?रि-टेंडर 17 फरवरी 2023 को किया गया।? जिसमें मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर और मे. शम्भू सिंह कन्ट्रक्शन सेक्टर 2 ने टेंडर भरा। तकनीकी समिति ने मे. शम्भू सिंह कन्ट्रक्शन का दस्तावेज कम होना बनाकर टेंडर से बाहर कर दिया। तो सिर्फ मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर ही बचा। जिसे ठेका दे दिया गया।

### रेट निगोशिएशन किए और मात्र 15 रुपए घटाए

मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट नागपुर ने ऑनलाइन रेट 1130 रुपए प्रति टन भरा था। वार्षिक दर 10.84 करोड़ रुपए था। खाद के लाभांश के रूप में 9.76 लाख रुपए कटौती के बाद 98.71 लाख रुपए ठेकेदार को दिया गया। जो कि 29.50 लाख रुपए निविदा राशि से ज्यादा था। इसलिए 21 मार्च 2023 को एमआईसी के प्रस्ताव क्रमांक 17 निगोशिएशन के प्रस्ताव को सर्व स?म्मति से पास किया गया। और फिर ठेका एजेंसी के दर में मात्र 15 रुपए कम किए। ठेकेदार का रेट 1130 रुपए प्रति टन को कम कर 1115 रुपए के हिसाब से वर्क आर्डर दे दिया गया।

निगम प्रशासन ने मे.अर्बन एनवायरो वेस्ट को 1115 रुपए प्रति टन की दर से ठेका दिया। जबकि इसी काम को इससे पहले मे. रमन ठेकेदार 721 रुपए प्रति टन के दर से करना था। सीधे-सीधे नागपुर की एजेंसी को 394 रुपए प्रति टन अधिक रेट में ठेका दिया गया। 1.07 करोड़ रुपए वार्षिक मूल्य पर ठेका दिया गया। इसमें खाद के लाभांश के रूप में 9.76 लाख रुपए वार्षिक कटौती करने के बाद 98.71 लाख रुपए ठेकेदार को दिया गया। जबकि यही काम रमन ठेकेदार 69.21 लाख रुपए में करता था। मतलब नागपुर की एजेंसी को 29.50 लाख रुपए ज्यादा में ठेका दिया गया। नगर निगम इसी काम को पहले जब रमन ठेकेदार काम कर रहा था तब वित्तीय वर्ष में खाद के रूप में मिलने वाला लाभांश की राशि 2200 रुपए प्रति टन था।

# छत्तीसगढ़-गोवा व्यापारिक रिश्तों को नई उड़ान

### छत्तीसगढ़ चेंबर और गोवा चेंबर के बीच ऐतिहासिक रू, निवेश और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा



**रायपुर।** छत्तीसगढ़ और गोवा के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (ष्टष्टष्ठ) और गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स (लष्टष्ठ) के बीच बुधवार को ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (रूश्व) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों राज्यों के उद्योग, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

इस एमओयू पर छत्तीसगढ़ चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी तथा गोवा चेंबर के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों ने इसे व्यापारिक सहयोग की नई शुरुआत करार दिया।

### क्या है समझौते का उद्देश्य

इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ और गोवा के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना, आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना और दोनों राज्यों के व्यापारियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जिससे वे एक-दूसरे के राज्यों में व्यवसाय, उद्योग और निवेश कर सकें।

### व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

समझौते के तहत दोनों चेंबर अपने-अपने राज्यों के उद्यमियों को व्यापारिक जानकारी, नेटवर्किंग, तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे। इससे छत्तीसगढ़ में नए निवेश आने की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं गोवा के व्यापारियों को भी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और व्यावसायिक परिवेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार यह साझेदारी उद्योग, व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देगी। दोनों राज्यों के बीच आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

छत्तीसगढ़ चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि यह एमओयू केवल एक औपचारिक समझौता नहीं, बल्कि दो राज्यों के आर्थिक विकास की मजबूत नींव है। वहीं गोवा चेंबर के प्रतिनिधियों ने इसे दीर्घकालिक और पारस्परिक लाभ वाला सहयोग बताया।

यह एमओयू छत्तीसगढ़ और गोवा के बीच व्यापारिक सेतु का काम करेगा और आने वाले समय में दोनों राज्यों को औद्योगिक और व्यावसायिक विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।

# गायत्री साक्षात कामधेनु है- सुरेश दीन

### 108 पार्थिव शिव लिंग का रुद्राभिषेक कर पूर्णाहुति हुआ

**निकुम।** गायत्री प्रज्ञा पीठ निकुम में शिव पुराण की कथा मे शिव गायत्री मंत्र जाप से कथा पंडाल में 108 पार्थिव शिवलिंग* का रुद्राभिषेक श्रद्धालुओं ने किया, वही शिव कथा मां गायत्री की महिमा बताते हुए प्रज्ञा पुत्र सुरेश कुमार दीन ने कहा कि वेदों की उत्पति के कारण इन्हें वेदमाता कहा जाता है, समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री हैं इस कारण गायत्री को ज्ञान-गंगा भी कहा जाता है ,माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। मां गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रुप में की। आरंभ में गायत्री सिर्फदेवताओं तक सीमित थी लेकिन जिस प्रकार भगीरथ कड़े तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना कर मां गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पंहुचाया वेद, शास्त्र और पुराण तो गायत्री मां की महिमा गाते ही हैं। अथर्ववेद में मां गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। वही सभी को महा भंडारा में भोजन प्रसादी मिला, इस अवसर पर माधव प्रसाद देशमुख ने कहा सभी मिलकर धर्म रथ में सहयोग किए, वही प्रज्ञा पुत्र हर सेवक मेश्राम ने कहा की सभी गायत्री मंत्र महामंत्र है इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं, घर समाज में संस्कार से गुरुदेव आचार्य श्री राम के विचारों से नए युग की शुरुवात हो, इस पर आयोजक प्रमुख के वरिष्ठ चिमनलाल देशमुख पंचराम देशमुख माधव प्रसाद देशमुख, निखिल साहू, हेमराज निर्मलकर, रेखा मेश्राम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे।

# उद्यानिकी खेती से बदली किसान की आर्थिक तस्वीर

### धान की तुलना में स्ट्रॉबेरी की खेती में डबल मुनाफा

### तकनीकी मार्गदर्शन, शासन की सब्सिडी से घटा खर्च, बढ़ी आमदनी



**रायपुर।** जिले में शासन की उद्यानिकी प्रोत्साहन योजनाओं से किसान अब परंपरागत खेती की सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब किसान केवल धान पर निर्भर न रहकर अधिक लाभ देने वाली फसलों को अपना रहे हैं। किसान लाल बहादुर सिंह बताया कि ढाई एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई है। इससे उन्हें करीब 9 लाख रुपये की आमदनी होने का अनुमान है।

सरगुजा जिले के भगवानपुरखुर्द निवासी किसान लाल बहादुर सिंह ने भी इसी सोच के साथ खेती में नवाचार अपनाया और आज वे एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उन्नत किसान के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

### धान से उद्यानिकी की ओर किया सफल बदलाव

कृषक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वर्षों से धान की खेती करने के बाद भी अपेक्षाकृत सीमित लाभ ही मिल पाता था। लागत बढ़ने और मौसम पर निर्भरता के कारण मुनाफा कम हो जाता था। इसी बीच उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसल की जानकारी दी और इसके फायदे समझाए। इससे उन्हें अपनी खेती में बदलाव करने की प्रेरणा मिली।

### छोटे क्षेत्र से शुरुआत, बड़े रकबे तक विस्तार

उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत उन्होंने मात्र 50 डिसमिल क्षेत्र से की थी। लाभ मिलने पर अगले वर्ष एक एकड़ में खेती की और फिर तीसरे व चौथे वर्ष इसे बढ़ाकर ढाई एकड़ तक कर दिया। वर्तमान में वे ढाई एकड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की सफल खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है।

### स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत कम अधिक मुनाफा

कृषक श्री सिंह ने बताया कि ढाई एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई है। इससे उन्हें करीब 9 लाख रुपये की आमदनी होने का अनुमान है। लागत निकालने के बाद लगभग 7 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि यही ढाई एकड़ यदि धान की खेती में लगाया जाता, तो लगभग 90 क्विंटल उत्पादन होता, जिससे शासकीय उपार्जन केन्द्र में बेचने पर करीब 3 लाख रुपये की आमदनी होती। धान की खेती में लगभग 1 लाख रुपये की लागत आने के बाद शुद्ध लाभ मात्र 2 लाख रुपये के आसपास ही रहता।

### उद्यानिकी में सब्सिडी से घटा खर्च, बढ़ा लाभ

किसान लाल बहादुर सिंह ने बताया कि उद्यानिकी विभाग की इस योजना के अंतर्गत पौध, खाद और बीज की राशि डीबीटी के माध्यम से वापस कर दी जाती है। उन्हें लगभग 80 से 85 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। विभाग द्वारा समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिससे खेती और अधिक सफल हो रही है।

लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वे पौधे स्वयं मंगवाते हैं और उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खेती करते हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा खेत का निरीक्षण कर आवश्यक सलाह दी जाती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है और बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है।

# सिख समाज प्रीमियर लीग 2026 में समाजसेवियों की रही उल्लेखनीय उपस्थिति

**दुर्ग।** सुराना कॉलेज ग्राउंड, दुर्ग में आयोजित सिख समाज प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन उत्साह, खेल भावना और सामाजिक एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर एवं सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह अपने परिवार इंदर सहित कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सर्व समाज कल्याण समिति के महासचिव मलकीत सिंह, जोगा राव, शाहनवाज़ कुरैशी, अनिल चौधरी, राम हिंदरिया, इंद्रजीत सिंह 'चिंटू', रमन राव, सोम सिंह, पंकज सहित परिवार इंदर के अन्य सदस्यों ने भी मैच का आनंद लेते हुए सक्रिय सहभागिता निभाई।

खेल आयोजन के दौरान इंद्रजीत सिंह ने आयोजकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज के युवाओं में एकता, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देते हैं। साथ ही युवाओं में अपने धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने में ऐसे कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने सिख समाज प्रीमियर लीग के सफल आयोजन के लिए आयोजक समिति को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा।

# वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी टी-20 सीरीज :ईशान किशन नंबर-3 पर उतरेंगे, न्यूजीलैंड से मुकाबला आज

**नागपुर।** भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को इस साल का पहला टी-20 मैच खेलेगी। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट मैदान पर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

5 मैचों की टी-20 सीरीज भारत की वर्ल्ड कप तैयारियों का फाइनल टेस्ट भी साबित होगा, क्योंकि टीम इंडिया को 7 फरवरी से अपने घर में टी-20 वर्ल्ड कप खेलना है। इसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी फॉर्म तलाशेंगे।

वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म दिखेंगे। इस सीरीज से जसप्रीत बुमराह भी वापसी कर रहे हैं। तेज गेंदबाज बुमराह को कीवियों के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम दिया गया था।

वनडे सीरीज का हिसाब चुकता करने का मौका भारत के पास वनडे सीरीज में मिली हार का हिसाब चुकता करने का मौका है। उसे 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-2 की पराजय झेलनी पड़ी है।

सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर नजरें होंगी कप्तान सूर्यकुमार यादव के फॉर्म पर नजरें होंगी। वे पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। पिछले 19 मैचों में एक भी फिफ्टी नहीं लगा सके। उन्होंने 218 रन बनाए।

तिलक चोटिल, ईशान को मौका तिलक वर्मा चोट के कारण टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ईशान किशन को नंबर-3 पर मौका मिलेगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कन्फर्म किया कि ईशान ही टॉप-3 में उतरेंगे।

पंड्या-बुमराह वापसी कर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। पंड्या के आने से टीम बैलेंस है। टीम प्रबंधन एक स्पेशलिस्ट बैटर या बॉलर को खिला सकता है।

टीम इंडिया ने घर में 63वां मैच जीते भारतीय टीम हेड-टु-हेड रिकॉर्ड में न्यूजीलैंड से आगे है। टीम ने 48वां मैच जीते हैं, जबकि 40वां मैच गंवाए हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इनमें से 12 मैच भारतीय टीम के पक्ष में रहे हैं, जबकि 10वां मैच कीवियों ने जीते हैं। 3 मैच टाई रहे हैं। होम वैन्यूज पर भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत ज्यादा है। टीम ने घर में 63वां मैच जीते हैं। टीम ने 11 में से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 4 में उसे पराजय झेलनी पड़ी है।

स्लो रहेगी नागपुर की पिच नागपुर की पिच धीमी रहती है। यहां उछाल भी कम होगा। ऐसे में शुरुआत में पेसर्स को थोड़ी मदद मिलेगी। बाद में बैटिंग आसान हो जाएगी। इस पिच में स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी।

यहां बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मैच जीते हैं। जबकि 4 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के नाम रहे हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 146 रहा है। जोकि दूसरी पारी में 125 रह जाता है यानी कि चेज करना आसान नहीं होगा।

नागपुर में बारिश के आसार नहीं बारिश के आसार न के बराबर हैं। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री हो सकता है। शाम में हल्की ओस रहेगी।

# दक्षिण अफ्रीका ने बनाया अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर

**विंडहोक (नामिबिया)।** अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान से पहला मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया. सोमवार 19 जनवरी को हाई परफॉर्मेंस ओवल में तंजानिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने 397/5 का बड़ा स्कोर बनाया, जो अब आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले इसी सीजन में श्रीलंका ने जापान के खिलाफ 391 रन बनाए थे.

इसके अलावा यह टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल भी है. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 2012 में नामीबिया के खिलाफ अंडर -19 वर्ल्ड कप 359/6 का स्कोर किया था. दूसरी ओर यह टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से अब तक का आठवां सबसे बड़ा स्कोर है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, जिनसे 2002 में केन्या के खिलाफ 6 विकेट पर 480 रन बनाए थे.

कप्तान मोहम्मद बुलबुलिया और जेसन रोल्स के शतकों की वजह से साउथ अफ्रीका इस बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा. बुलबुलिया ने 108 गेंद पर 108 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था. जबकि रोल्स 101 गेंदों पर 125 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्होंने अपनी पारी में दस चौके और पांच छक्के लगाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 201 रन की पार्टनरशिप की. इसके अलावा पॉल जेम्स ने सिर्फ 18 गेंदों पर दो चौकों और पांच छक्कों की मदद से 46 रन बनाए, जिससे प्रोटियाज 400 रन के आंकड़े से सिर्फ तीन रन दूर रह गए.

397 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तंजानिया की पूरी टीम 32.2 ओवर में केवल 68 रनों पर ही ढेर हो गई. जिसकी वजह से उन्हें 329 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका अब 22 जनवरी को उसी जगह पर अपने आखिरी ग्रुप डी गेम में वेस्टइंडीज से भिड़ेगा.

# डब्ल्यूपीएल 2026 : आरसीबी ने दर्ज की लगातार पांचवीं जीत, गुजरात को हराकर पहुंची प्लेऑफ में

**वडोदरा।** महिला प्रिमियर लीग 2026 (डब्ल्यूपीएल 2026) का 12वां मैच सोमवार को वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात जायंट्स (जीजी) बीच खेला गया. जिसमें सायली सतघरे के शानदार तीन विकेट और गौतमी नाइक की दमदार बैटिंग परफॉर्मेंस की बदौलत आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हरा दिया. ये इस सीजन आरसीबी की लगातार पांचवी जीत है. जिसकी वजह से वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है.

इस जीत के सात आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा छह जीत का नया रिकॉर्ड भी बनाया. इसने 2023 और 2023-24 में मुंबई इंडियंस के पांच मैचों की पिछली स्ट्रीक और 2024-25 में आरसीबी की अपनी स्ट्रीक को पीछे छोड़ दिया.

शाम को, गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने आरसीबी को पहले बैटिंग करने के लिए कहा और पिछले मैच की तरह ही उनकी पारी की शुरुआत खराब रही. मैच के पहले ओवर में, ग्रेस हैरिस एक रन बनाकर रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनीं, और अगले ही ओवर में जॉर्जिया वोल को काश्वी गौतम ने आउट कर दिया, जिससे आरसीबी पर शुरुआत में ही दबाव आ गया. कप्तान स्मृति मंधाना के साथ गौतमी नाइक आईं और दोनों खिलाड़ियों ने पावरप्ले खत्म होने तक टीम की पारी को संभालने की कोशिश की.

सिर्फ नौ रन पर दो विकेट गिरने के बाद, आरसीबी ने पहले छह ओवर में 39 रन बनाए. इसके बाद मंधाना और नाइक ने 45 गेंदों पर बहुत जरूरी 60 रनों की पार्टनरशिप की, जो दसवें ओवर में टूटी जब गार्डनर खुद बॉलिंग करने आईं और मंधाना को 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.

नाइक उस समय भी टिकी रहीं और आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाया, चौथे विकेट के लिए ऋचा घोष के साथ शानदार 69 रनों की पार्टनरशिप की, जब तक कि नाइक ने 42 गेंदों पर अपना पहला डब्ल्यूपीएल अर्धशतक पूरा नहीं कर लिया. नाइक आखिरकार 55 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हुईं. ऋचा ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आरसीबी की शानदार पारी में योगदान दिया, और राधा यादव और श्रेयांका पाटिल की कुछ तेज पारियों की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में 178 रन बनाए. इसके बाद आरसीबी ने 178 रनों को डिफेंड करते हुए शुरुआत से ही जबरदस्त आक्रामक प्रदर्शन किया. सायली सतघरे ने दूसरे ओवर में दो विकेट लेकर इस आक्रामकता का पूरा फायदा उठाया. सतघरे की यह शानदार उपलब्धि तब हासिल हुई जब उन्होंने दोनों खिलाड़ियों, बेथ मूनी (3 रन) और सोफी डिवाइन (0 रन) को आउट किया. अगले ओवर में, लॉरेन बेल आरसीबी के अटैक में शामिल हुईं और अपने दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर कनिका आहूजा को आउट कर दिया, जिससे गुजरात तीन ओवर के बाद 5 रन पर 3 विकेट की मुश्किल स्थिति में आ गया. हालांकि अनुष्का शर्मा और गार्डनर ने कुछ अच्छी बैटिंग करके पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन चौथे विकेट के लिए उनके बीच 25 गेंदों में 29 रन की साझेदारी ज्यादा देर नहीं चली।

# बाजार की पाठशाला : आईपीओ में जीएमपी क्या होता है, रजिस्ट्रार और बुक रनिंग लीड मैनेजर का क्या काम होता है?

**मुंबई।** शेयर बाजार में अधिकतर निवेशक कम समय में मोटा मुनाफा कमाने के लिए अक्सर आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) का रुख करते हैं। लेकिन, आईपीओ में निवेश करने से पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनके बारे में निवेशकों को जानना बेहद जरूरी होता है। इनमें सबसे आम सवाल जिसको लेकर अक्सर निवेशकों के मन में संशय रहता है, वह है जीएमपी क्या होता है, रजिस्ट्रार की भूमिका क्या है और बुक रनिंग लीड मैनेजर आखिर क्या करता है। सही जानकारी के बिना आईपीओ में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है।

आईपीओ में जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) एक अनौपचारिक संकेत होता है, जो यह बताता है कि किसी कंपनी के शेयर लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड यानी ग्रे मार्केट में कितने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए किसी आईपीओ का इश्यू प्राइस 100 रुपए है और उसका जीएमपी 40 रुपए चल रहा है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि शेयर की लिस्टिंग करीब 140 रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ बाजार की धारणा पर आधारित होता है, इसे न तो सेबी नियंत्रित करता है और न ही इसकी कोई गारंटी होती है। कई बार अच्छा जीएमपी होने के बावजूद शेयर कमजोर लिस्ट होते हैं और कभी-कभी बिना जीएमपी के भी शानदार लिस्टिंग देखने को मिलती है।

वहीं, रजिस्ट्रार वह संस्था होती है जो आईपीओ से जुड़े प्रशासनिक और ऑपरेशनल कार्यों को संभालती है। इसमें निवेशकों से मिले आवेदन, शेयरों का आवंटन (अलॉटमेंट), रिफंड की प्रक्रिया और डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करना शामिल होता है। आसान शब्दों में कहें तो रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि किस निवेशक को कितने शेयर मिले और पैसा सही तरीके से एडजस्ट हो। सरल शब्दों में कहें तो रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि शेयर आवंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष, सटीक और समय पर पूरी हो। भारत में लिंक इनटाइम, केफिन टेक्नोलॉजीज और एमयूएफजी इंटाइम जैसी कंपनियां प्रमुख रजिस्ट्रार हैं।

अब बात करते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) की। यह आईपीओ की पूरी योजना और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है। यह आमतौर पर बड़ी निवेश बैंक या ब्रोकरेज फर्म होती हैं, जो कंपनी को यह तय करने में मदद करती हैं कि आईपीओ का साइज कितना हो, प्राइस बैंड क्या रखा जाए और निवेशकों से कितनी मांग आ सकती है। बीआरएलएम ही संस्थागत निवेशकों से बातचीत करता है और पूरे इश्यू को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स जैसी संस्थाएं अक्सर इस भूमिका में दिखती हैं।

इसके अलावा, बुक रनिंग लीड मैनेजर आईपीओ की मार्केटिंग करता है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित करता है और अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार तथा अन्य मध्यस्थों के साथ समन्वय बनाकर काम करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरी हो। बाजार के जानकारों के अनुसार, आईपीओ प्रक्रिया में रजिस्ट्रार और बुक रनिंग लीड मैनेजर, दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इनके सही तालमेल से ही कोई आईपीओ सफल बन पाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में निवेश करना सही रणनीति नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मुनाफे का रिकॉर्ड, कर्ज की स्थिति, भविष्य की योजनाएं और रिस्क फैक्टर भी उतने ही अहम होते हैं। आईपीओ के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसे सेबी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज की साइट्स पर उपलब्ध कराया जाता है।

# साइना नेहवाल ने की रिटायरमेंट की पुष्टि, पिछले दो साल से थीं कोर्ट से दूर

**नईदिल्ली।** ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने आखिरकार अपने रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी है. पिछले दो सालों से खेल से दूर रहने के बावजूद साइना ने कभी औपचारिक रूप से बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में इस पर बात करते हुए कहा कि उनका शरीर अब इस खेल की शारीरिक मांगों को पूरा नहीं कर सकता.

पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल ने एक पॉडकास्ट में कहा, %मैंने दो साल पहले खेलना बंद कर दिया था, मुझे सच में लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेल में एंट्री की थी और अपनी शर्तों पर ही इसे छोड़ा, इसलिए इसकी घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी. अगर आप अब और खेलने में सक्षम नहीं हैं, तो बस इतना ही, यह ठीक है.% साइना 2015 में वर्लड नंबर वन शटलर बनी थी.

साइना ने ये भी बताया कि घुटना खराब होने के कारण वह लंबे समय तक हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थीं, और मुझे नहीं लगा कि मेरे रिटायरमेंट की घोषणा करना इतना बड़ा मामला है. मुझे बस लगा कि मेरा समय खत्म हो गया है क्योंकि मैं ज्यादा जोर नहीं खेल सकती थी, मेरा घुटना पहले की तरह जोर नहीं लगा पा रहा था.%

उन्होंने आगे कहा, %आप दुनिया में सबसे अच्छा बनने के लिए आठ से नौ घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन अब मेरा घुटना एक या दो घंटे में ही जवाब दे रहा था. इसमें सूजन आ जाती थी और उसके बाद जोर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था. इसलिए मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया. मैं अब और जोर नहीं लगा सकती.%

साइन ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं. उन्होंने 2012 में लंदन में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था. वह दुनिया में नंबर एक रैंक पर भी थीं और उन्होंने 2010 और 2018 में नई दिल्ली और गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था. इसके अलावा उन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था.

# रबी फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 650 लाख हेक्टेयर के पार

**नई दिल्ली।** रबी फसलों के तहत बुआई का कुल क्षेत्रफल (16 जनवरी तक) 20.88 लाख हेक्टेयर बढ़कर 652.33 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 631.45 लाख हेक्टेयर था। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई।

मंत्रालय ने बताया कि बुआई का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और खाने-पीने की चीजों की महंगाई को भी नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल इसी दौरान 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में गेहूं का क्षेत्रफल 6.13 लाख हेक्टेयर बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। उड़द, मसूर, चना और मूंग जैसी दालों की खेती का क्षेत्रफल पिछले साल इसी अवधि के 133.18 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.82 लाख हेक्टेयर अधिक यानी 137 लाख हेक्टेयर हो गया है।

ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज या बाजरे की खेती का क्षेत्रफल पिछले साल की इसी अवधि के 55.93 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस सीजन में अब तक 2.79 लाख हेक्टेयर बढ़कर 58.72 लाख हेक्टेयर हो गया है।

सरसों और राई जैसी तिलहन फसलों का क्षेत्रफल पिछले साल इसी अवधि के 93.33 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.53 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी के साथ 96.86 लाख हेक्टेयर हो गया है।

इस सीजन में खेती का क्षेत्रफल बढ़ने की वजह मानसून सीजन में अच्छी बारिश का होना है, जिसने उन इलाकों में भी बुआई को आसान बना दिया है, जहां कम बारिश के कारण बुआई नहीं हो पाती थी।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने पिछले साल 1 अक्टूबर को 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य बुवाई के मौसम से काफी पहले घोषित किए जाते हैं, जिससे किसान उसी हिसाब से अपनी फसल की योजना बना सकें और अपनी कमाई बढ़ा सकें। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की गई है, इसके बाद मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए क्रमशः 250 रुपए प्रति क्विंटल, 225 रुपए प्रति क्विंटल, 170 रुपए प्रति क्विंटल और 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

# रोहित-कोहली के केंद्रीय अनुबंध में हो सकता है बदलाव, ग्रेड-बी में जाने की संभावना

**नई दिल्ली।** भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अपनी वार्षिक केंद्रीय अनुबंध प्रणाली में बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति द्वारा सुझाए गए इन बदलावों में ग्रेड ए + श्रेणी को समाप्त करना और केवल तीन श्रेणियां (ग्रेड- ए, बी, सी) बनाए रखना शामिल है। अगर अगली शीर्ष परिषद की बैठक में इसे मंजूरी मिलती है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड-बी में भेजे जाने की पूरी संभावना है। बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध भारतीय क्रिकेटरों को दिए जाने वाले वार्षिक अनुबंध हैं। इन्हें 4 ग्रेड में बांटा गया है, जिनमें ए +, ए, बी और सी शामिल हैं। प्रत्येक ग्रेड में मैच फीस के अतिरिक्त एक भारी वार्षिक शुल्क शामिल होता है। वर्तमान संरचना के अनुसार, ए + ग्रेड के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये, ए ग्रेड के खिलाड़ियों को 5 करोड़, बी ग्रेड के खिलाड़ियों को 3 करोड़ और सी ग्रेड के खिलाड़ियों को 1 करोड़ दिए जाते हैं।

चयन समिति द्वारा प्रस्तावित बदलावों से अनुबंध संरचना में बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो ए, बी और सी के रूप में केवल तीन ग्रेड रह जाएंगी। इससे कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों को ग्रेड- बी में रखा जा सकता है। इसका कारण है कि वर्तमान में ये दोनों अनुभवी बल्लेबाज केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं। ये दोनों ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इनकी ग्रेड कम की जा सकती है।

फिलहाल, ग्रेड- ए + में रोहित, कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे शीर्ष क्रिकेटर शामिल हैं। हालांकि, बुमराह ही फिलहाल तीनों प्रारूपों में सक्रिय हैं, लेकिन उनके काम के बोझ को लेकर विवाद बना हुआ है। जडेजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगर बीसीसीआई ए + ग्रेड को खत्म करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इन खिलाड़ियों को कम वेतन वाली श्रेणियों में डाला जा सकता है।

ग्रेड-ए में ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या शामिल हैं। सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जयसवाल को ग्रेड-बी में रखा गया है। इसी तरह रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ग्रेड- सी में शामिल हैं।

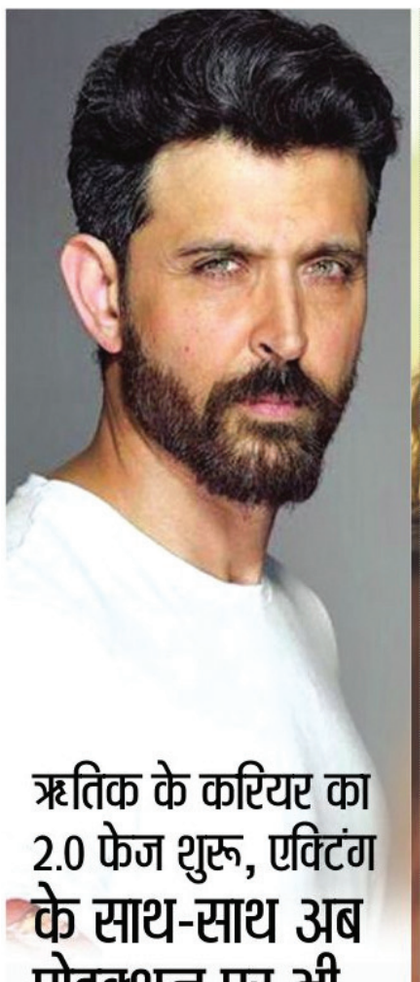

## ऋतिक के करियर का 2.0 फेज शुरू, एक्टिंग के साथ-साथ अब प्रोडक्शन पर भी लगा रहे बड़ा दांव

ऋतिक रोशन दो दशक से ज्यादा समय तक हिंदी सिनेमा में बतौर सुपरस्टार अपनी मजबूत बनाए हुए हैं। अब वह अपने करियर के अगले फेज की तैयारी में जुट गए हैं। 2026-27 के लिए तैयार उनका रोडमैप साफ संकेत देता है कि अभिनय के साथ-साथ अब उनका फोकस फिल्म निर्माण और कंटेंट आईपी पर भी है। अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए ऋतिक डिजिटल और फिल्म प्रोडक्शन स्पेस में भी निवेश कर रहे हैं, ताकि वह सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि कंटेंट ओनर के रूप में भी खुद को स्थापित कर सकें। स्टॉर्म बतौर निर्माता ऋतिक का डेब्यू प्रोजेक्ट है। अक्टूबर 2025 में स्ट्रीमिंग कंटेंट की आधिकारिक घोषणा के बाद इस थ्रिलर सीरीज की शूटिंग नवंबर में मुंबई में शुरू हुई थी और इसे फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस सीरीज को टब्बर फेम अजीतपाल सिंह ने क्रिएट और डायरेक्ट किया है। बताया जाता है कि ऋतिक और अजीतपाल ने इस कहानी को लगभग तीन साल तक डेवलप किया है। यह सीरीज प्राइम वीडियो और HRX फिल्म्स के बीच हुई बड़ी प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप का हिस्सा है। इसे ऋतिक के डिजिटल कदम की मजबूत शुरुआत माना जा रहा है।

### एक्टिंग के लिए हाई-बजट प्रोजेक्ट चुन रहे ऋतिक

ऋतिक ने आने वाले दो वर्षों के लिए बेहद चुनिंदा हाई-बजट प्रोजेक्ट्स चुने हैं। वॉर 3 को लेकर भले ही अनाउंसमेंट नहीं हुई हो, लेकिन इसे 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। कृष 4 पर भी काम तेजी से जारी है।

### बैलेंस पोर्टफोलियो की ओर करियर ले जा रहे सुपरस्टार

ट्रेड के मुताबिक, ऋतिक का यह ट्रांजिशन पूरी तरह प्लांड है। बदलते दौर में जहां सुपरस्टार्स के लिए सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि डिजिटल राइट्स और आईपी ओनरशिप भी अहम हो गई है, वहीं ऋतिक अपने करियर को बैलेंस पोर्टफोलियो की ओर ले जा रहे हैं। एक तरफ वॉर 3 और कृष 4 जैसी मास अपील फिल्में, तो दूसरी तरफ स्टॉर्म जैसे कंटेंट-ड्रिवन प्रोजेक्ट्स। आने वाले समय में यही संतुलन तय करेगा कि ऋतिक बतौर निर्माता कितने प्रभावी होते हैं।

## पहली फिल्म है तो किरदार नहीं, काम मिलना सबसे जरूरी होता है

पारुल गुलाटी ने कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा के साथ किस किस को प्यार करूं 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अपने किरदार और शूटिंग के अनुभवों को लेकर पारुल ने बातचीत की।

**इस फिल्म से आप कैसे जुड़ीं?**
इस फिल्म से मैं अपनी एजेंसी के जरिए जुड़ी थी। वहीं मुझे पता चला कि एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नैरेशन के लिए जाना होगा, तो हमारे डायरेक्टर अनुकल्प जी के साथ मेरा नैरेशन हुआ। कहानी सुनते समय हमारी हंसी रुकी ही नहीं। सबसे खास बात यह थी कि कपिल शर्मा इसमें है, यह जानकर बहुत खुशी हुई। साथ ही अब्बास मस्तान भी इस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। कुल मिलाकर यह मेरे लिए एक परफेक्ट प्रोजेक्ट था, बिल्कुल वैसे जैसा मैं अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में सोचती थी।

**कॉमेडी में टाइमिंग्स के लिए क्या किया?**
इसके लिए मैंने कोई अलग तैयारी नहीं की थी। सच कहूं तो मैंने कपिल शर्मा शो भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मुझे डर लगेगा।

**सेट पर आपकी बॉन्डिंग कैसी थी?**
कपिल काफी मजाक-मस्ती करते रहते हैं। जब भी वो सेट पर होते थे, मुझे लगता था कि वो मुझसे उम्र और अनुभव में बहुत बड़े हैं, इसलिए उनके साथ मैं ज्यादा हमस्ती नहीं की।

**अच्छा किरदार ज्यादा मायने रखता है या बड़ा प्रोजेक्ट?**
अगर यह पहली फिल्म है, तो सबसे अहम है कि आपको काम मिल रहा है। इस फिल्म में मुझे किरदार की अहमियत के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि यह कॉमेडी फिल्म थी।

## प्रलय में रणवीर संग बन सकती है आलिया की जोड़ी

साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर देने के बाद रणवीर सिंह अब अपनी अगली बड़ी फिल्म प्रलय की तैयारी में जुटने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक... मार्च 2026 में धुरंधर का दूसरा पार्ट रिलीज होगा और इसके बाद रणवीर प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे। हालांकि फिल्म को लेकर अभी ज्यादा ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी हीरोइन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रलय में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट नजर आ सकती हैं। इससे पहले दोनों ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में साथ काम किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता करेंगे और फीमेल लीड सूत्रों के मुताबिक फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद आलिया हैं। म में आलिया का किरदार सिर्फ लव इंटरेस्ट तक सीमित नहीं होगा। उनका रोल कहानी का अहम हिस्सा होगा, जो एक टूटती हुई दुनिया में हीरो के विचारों को चुनौती देगा। डायरेक्टर का मानना है कि इस तरह के दमदार और एक्सपेरिमेंटल रोल के लिए आलिया से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म के लिए बड़े स्तर पर सेट तैयार किए जाएंगे, जहां शहर को पुराना और वीरान दिखाने के लिए फिजिकल सेट्स के साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा।

## चोट से उबरने के बाद ईथा पर फिर जुटीं श्रद्धा

साल 2026 श्रद्धा कपूर के करियर के लिए बेहद कपूर हम और व्यस्त रहने वाला है। श्रद्धा फिलहाल बायोपिक फिल्म ईथा के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग में जुटी हैं, जिसमें वह मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं। मार्च 2026 के अंत तक शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है। डांस सीक्वेंस के दौरान लगी चोट के कारण शूट कुछ समय के लिए रुका था लेकिन अब काम फिर रफ्तार पकड़ चुका है। यह फिल्म श्रद्धा के लिए खास है, क्योंकि इसमें उन्हें एक लोक कलाकार की जिंदगी, शारीरिक भाषा और संघर्ष को परदे पर उतारना है। ईथा के बाद श्रद्धा अप्रैल 2026 से अपनी बहुचर्चित फैंटेसी फिल्म नागिन की शूटिंग शुरू कर सकती हैं। लंबे समय से प्री-प्रोडक्शन और वीएफएक्स पर काम कर रही इस फिल्म में श्रद्धा इच्छाधारी नागिन के किरदार में नजर आएंगी। चर्चा है कि नागिन सिर्फ एक स्टैंडअलोन फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़े फैंटेसी यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है। सोशल मीडिया पर यह थ्योरी भी चल रही है कि इस फिल्म का कनेक्शन श्रद्धा के सुपरहिट किरदार स्त्री से जोड़ा जा सकता है।
स्त्री 3 की स्क्रिप्ट पर तेजी हो रहा काम, श्रद्धा की हिट फ्रेंचाइज स्त्री के तीसरे भाग को लेकर भी हलचल तेज है। स्त्री 2 की बड़ी सफलता के बाद मेकर्स अब स्त्री 3 की स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर तेजी से काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, इस बार श्रद्धा के किरदार की शक्तियों के स्रोत और उसकी असली पहचान का खुलासा हो सकता है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नागिन और स्त्री के बीच किसी तरह का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है।

## फिल्म द ग्रेट एस्केपः फरार में मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे होगा नवाज का रोल

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म द ग्रेट एस्केपः फरार अपने अनोखे कॉन्सेप्ट, ग्लोबल टीम और तकनीकी तैयारी के कारण चर्चा में है। कुशाग्र शर्मा निर्देशित यह एस्केप-थ्रिलर ताकत से ज्यादा दिमाग, विज्ञान और रणनीति पर आधारित है। फिल्म एक आम-से दिखने वाले फिजिक्स प्रोफेसर की कहानी है, जो अपनी समझदारी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से अंतरराष्ट्रीय संकट से निकलने की कोशिश करता है। फिल्म में नवाजुद्दीन का किरदार निर्देशक ने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसी इंटेलिजेंट अप्रोच से जोड़ा है, हालांकि समानता सिर्फ रणनीति और प्लानिंग तक सीमित है। कहानी और ट्रीटमेंट पूरी तरह भारतीय संदर्भ में है। नवाजुद्दीन ने फिजिक्स प्रोफेसर का रोल निभाते हुए संवादों से आगे बढ़कर कई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स समझे, सेट पर प्रयोग किए और किरदार को वास्तविक बनाने के लिए तकनीकी डिटेल्स पर खास मेहनत की। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका ग्लोबल एसोसिएशन है। हॉलीवुड एक्टर इलिया वोलोक फिल्म में मुख्य खलनायक हैं, जो मिशन इम्पॉसिबल, इंडियाना जोन्स और जेमिनी मैन जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। नवाजुद्दीन के साथ मलयालम स्टार निमिषा सजयन उनकी पत्नी का रोल निभा रही हैं। इसके अलावा यंगेस्ट नेशनल अवॉर्ड विनर त्रिशा भी इसका हिस्सा हैं। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा थाईलैंड, बैंकॉक और पटाया में शूट किया गया। लोकेशंस सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि कहानी की जरूरत के मुताबिक चुनी गई। शूट स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल में पूरा किया गया ताकि कंटिन्यूटी बरकरार रहे। एक्शन के लिए बैंकॉक के मशहूर एक्शन डायरेक्टर केचा खम्फाकदी को जोड़ा गया है, जो अल्लू अर्जुन की पुष्पा और शाहरुख खान की जवान का भी हिस्सा रह चुके हैं।

## हॉरर-कॉमेडी फिल्म होगी यामी की फिल्म नई नवेली

**हिंदी सिनेमा में इन दिनों हॉरर-कॉमेडी जॉनर बॉक्स ऑफिस की सबसे मजबूत कड़ी बन चुका है। ऐसे में इस ट्रेंड से जुड़ने वालों की फेहरिस्त में यामी गौतम का नाम भी शामिल हो गया है। ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुई गंभीर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म हक में दमदार परफॉर्मेंस के बाद यामी अब एक बिल्कुल अलग व हल्के-फुल्के अंदाज में आने की तैयारी कर रही हैं।**

शूटिंग फरवरी से शुरू करने की तैयारी है सूत्रों के मुताबिक, यामी को निर्देशक-निर्माता आनंद एल राय के अगले प्रोडक्शन के लिए साइन किया गया है। यह फिल्म एक हॉरर-कॉमेडी होगी, जिसका टाइटल नई नवेली बताया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग इसी साल फरवरी से शुरू होने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि नई नवेली, यामी और आनंद एल राय के प्रोडक्शन हाउस कलर येलो के बीच पहला कोलैबोरेशन होगा। फिल्म की कहानी भारतीय लोककथाओं और पौराणिक मान्यताओं से प्रेरित है। इसकी स्क्रिप्ट दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। शुरुआती चर्चाओं में इसे टू-हीरोइन फिल्म बताया जा रहा था, जिसमें यामी के साथ कृति सेनन का नाम सामने आया था। हालांकि, कृति अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं और फिल्म की पूरी कमान यामी ही अपने कंधों पर संभालेंगी।

### बड़े स्केल पर तैयार हो रहा प्रोजेक्ट

हक जैसी गंभीर फिल्म के बाद यामी एक ऐसी कहानी की तलाश में थी, जो मनोरंजन के साथ-साथ भावनात्मक असर भी छोड़े। नई नवेली में कॉमेडी के साथ रोमांच और इमोशन्स का संतुलित मेल देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्देशन तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुके बालाजी मोहन करेंगे, जो मारी (2015) जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं। यह फिल्म उनके हिंदी सिनेमा में डेब्यू का भी मौका होगी। आनंद एल राय बतौर निर्माता भी सुर्खियों में हैं। उनके बैनर तले बनी फिल्म तू या मैं की शूटिंग पूरी हो चुकी है। बेजॉय नांबियार निर्देशित इस फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव हैं। रोमांस, सर्वाइवल और थ्रिल के अनोखे मिश्रण वाली यह फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। हाल ही में जारी मोशन पोस्टर और टीजर अनाउंसमेंट ने फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। आनंद निर्मित यह फिल्म सीधे आज के युवाओं से जुड़ती है।

## तेरे इश्क में... के बाद फिर धनुष के साथ एक फिल्म करेंगे आनंद

आनंद एल राय और धनुष की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है। जानकारी है कि दोनों एक भव्य पीरियड एक्शन रोमांटिक फिल्म पर मंथन कर रहे हैं, जिसे बड़े स्केल और हाई-विजुअल कैनवास पर बनाया जाएगा, हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जबकि उनकी नखरेवाली भी कतार में है।

# संभागायुक्त राठौर ने मादक पदार्थों की रोकथाम व अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश

**स्कूल-कॉलेज परिसरों के आसपास स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने पर दिया जोर**

**ई-ऑफिस से बढ़ेगी पारदर्शिता और समय की होगी बचत**

**दुर्ग।** संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान एवं विभागीय अधिकारियों से ई-ऑफिस संचालन के संबंध में जानकारी ली। संभागायुक्त श्री राठौर ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल एवं कॉलेजों में नशा विरोधी कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। साथ ही निबंध, भाषण, पोस्टर, चित्रकला, नाटक एवं क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए। संभागायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। स्कूल और कॉलेजों के बाहर ठेलों पर तंबाकू, सिगरेट, गुटखा जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संभागायुक्त श्री राठौर ने त्रुटिरहित प्रश्नपत्र तैयार करने के निर्देश दिए और प्रश्न निर्माण के दौरान समुचित जांच-पड़ताल पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अभियान चलाकर अधिक से

अधिक छात्र-छात्राओं के आय, जाति, निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाना सुनिश्चित करने कहा। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्वच्छता को सुदृढ़ रखने के लिए एनएसएस, एनसीसी एवं स्काउट-गाइड के सहयोग पर जोर दिया। संभागायुक्त श्री राठौर ने सभी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों एवं शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण बढ़ने से आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्यवाही करें। उन्होंने सभी विभागों में आधार बेस्ड अटेंडेंस को प्राथमिकता के साथ लागू करने तथा विभागीय कार्यों को ई-ऑफिस के माध्यम से ही नोटशीट व पत्राचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार ई-ऑफिस से सम्बंधित प्रशिक्षण पुनः प्रदान कराने को कहा। ई-ऑफिस से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इसके अलावा संभाग स्तरीय कार्यालयों में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, आवारा मवेशियों पर नियंत्रण तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग को सभी पंचायतों में प्राथमिक सहकारी समितियों से शत-प्रतिशत जोड़ने के लिए कहा गया। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुमलाल यादव, उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

दुर्ग संभाग सहित छत्तीसगढ़ से प्रकाशित
होने खबर आलोक एवं सांध्य दैनिक नई दृष्टि

बिंदु परिवार और पत्रकार
आलोक तिवारी जी

हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

देवेंद्र यादव
सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,
विधायक भिलाई नगर

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंदु स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवाकर 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला भिलाई, दुर्ग, (छग)-490023 से प्रकाशित। संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।